नई दिल्ली । शनिवार, 25 जुलाई, 2026
आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक : 200/ मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
नई दिल्ली संस्करण

विश्व केसरी

सिर्फ पत्रकारिता...

vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwa_kesari_official

आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल यूथ हॉकी5एस एशियन चैंपियनशिप : भारतीय पुरुष टीम... @ विचार नीट के बवाल के बीच एक बड़ा सवाल : डॉक्टर बनने... @ व्यापार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते लगातार पांचवें...

सरकार का बड़ा एक्शन, 47 अधिकारी बर्खास्त, क्रिमिनल केस की तैयारी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

पेपरलीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में बड़ा बदलाव करने वाली है। बताया जा रहा है कि एजेंसी से जुड़े 47 लोगों को हटा दिया गया है और इससे पहले गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय ने दो सचिवों को बदला गया था।

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आमूलचूल पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अगले एक महीने के भीतर एजेंसी की संरचना में बड़े बदलाव किए जाएंगे। एनटीए के कामकाज और परीक्षा संचालन प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। खास तौर पर एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बदला जाएगा। यह बदलाव विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ऐसी लीक प्रूफ व्यवस्था तैयार करना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बने। एनटीए देश की कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं का आयोजन करती है। इनमें नीट, जेईई, सीयूईटी सहित लगभग 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं शामिल हैं। हाल ही में हुए नीट पेपर को सफलतापूर्व कराने की जिम्मेदारी भी एनटीए के पास ही थी। विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार का यह कदम परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर देश को भरोसा दिलाया था कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार कठोर कानून लेकर आने वाली है। इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। जल्द से इसे सदन में पेश किए जाने की भी संभावना है।

सीजेपी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई बात, शनिवार को दोबारा होगी चर्चा : जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की। दो घंटे चली बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि हर विषय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहां आए थे। बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। सरकार की ओर से मैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आए। हमने उनकी बातें सुनीं। हर विषय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई।' नड्डा ने कहा, 'उनकी 3 मुख्य मांगें और परीक्षाओं के लिए 5 सुधार के सुझाव थे। हमने उनसे कहा है कि हम शनिवार दोपहर फिर मिलेंगे और उन्हें सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में बताएंगे।' वहीं, सरकार के साथ बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, 'हमने सरकार के सामने पक्ष रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। पूरे देश में अलग-अलग आंदोलन चल रहे हैं और युवाओं में गुस्सा है। सभी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।' आशुतोष रांका ने बताया कि मांगों को लेकर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। शनिवार को दिन में फिर से सरकार के साथ बातचीत होगी। आशुतोष रांका ने यह भी कहा कि हमने सरकार को बताया है कि देशभर में प्रदर्शन चल रहे हैं। ये आगे वाले दिनों में और बढ़ेंगे। जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से बर्खास्तगी नहीं हुई तो और व्यापक प्रदर्शन होंगे। जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान करना होगा। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवजे (आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को) और छात्रों पर दर्ज एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।'

सख्त सजा दिलाने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

पेपर लीक मामला : संसद में जल्द होगा पेश

एजेंसी ■ नई दिल्ली

नीट पेपर लीक समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के मामलों में सजा को और सख्त बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देशभर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है।

दरअसल, कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार देर रात तीन मिनट का एक वीडियो संदेश जारी कर इस दिशा में बड़े संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कड़ी सजा देने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है। इससे देश के लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस समस्या से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पहले गुरुवार सुबह भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी की नजर अगले सप्ताह संसद पर रहेगी, जहां इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है। वहीं, नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उधर, केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया। सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने विनीत जोशी की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है।

भारत-रोमानिया ने साझा किए भविष्य के लक्ष्य : एमईए

रक्षा से व्यापार तक बढ़ेगा सहयोग

एजेंसी ■ नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव रोमानिया में भारत और रोमानिया ने व्यापार, रक्षा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की विशेष ब्रीफिंग में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों ने अगले तीन से पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की रोमानिया की राजकीय यात्रा पर विदेश मंत्रालय की विशेष ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के निमंत्रण पर भारत की राष्ट्रपति रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। यह उनकी तीन देशों की यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है। इससे पहले वह मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा कर चुकी हैं। जॉर्ज ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीन दशक से भी ज्यादा समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा है।

धर्मेंद्र प्रधान को हटाए बिना संसद में चर्चा नहीं : राहुल गांधी

मेरा माइक फिर से किया गया बंद

एजेंसी ■ नई दिल्ली

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक इस मुद्दे पर किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुझाव पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। संसदीय परंपरा के अनुसार, यदि किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसे जवाब देने का अधिकार होता है लेकिन जब वह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का जवाब देना चाहते थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने विपक्ष का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों पर कथित कार्रवाई और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जाता, तब तक विपक्ष किसी चर्चा या बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि विपक्ष नीट पेपर लीक मामले पर गंभीर बहस और जवाबदेही चाहता है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भविष्य में प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा संपन्न होने तक पेपर लीक रोकने के लिए क्या ठोस व्यवस्था की जाएगी।

हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरीं, 13 की मौत

गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं

एजेंसी ■ नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई। उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं। वहीं, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।

क्या मोदी सरकार से हो रही है सबसे बड़ी राजनीतिक चूक?

सुजीत कुमार ■ नई दिल्ली

देश के प्रमुख शहरों की सड़कों पर तेज़ी से उभर रहा छात्र-युवा आंदोलन अब केवल स्थानीय विरोध-प्रदर्शन भर नहीं रह गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरी केंद्रों में युवाओं की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति है। इसकी कोई एक केंद्रीय नेतृत्व संरचना नहीं है, फिर भी बेरोज़गारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएँ, शिक्षा की बढ़ती लागत, सीमित रोजगार अवसर, महंगाई और भविष्य को लेकर गहराती अनिश्चितता ने अलग-अलग शहरों के युवाओं को एक साझा बेचैनी में जोड़ दिया है। सोशल मीडिया ने इस असंतोष को अभूतपूर्व गति दी है। एक शहर में उठी आवाज़ कुछ ही घंटों में दूसरे शहरों तक पहुँच रही है और स्थानीय विरोध धीरे-धीरे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है।

भारत के राजनीतिक इतिहास में छात्र आंदोलनों ने कई बार सत्ता की दिशा बदली है। वर्ष 1974 में बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन में बदल गया। देखते ही देखते यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर गया और भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण बना। असम आंदोलन और मंडल आंदोलन भी इस बात के उदाहरण हैं कि जब युवाओं का असंतोष व्यापक जनसमर्थन हासिल करता है, तो उसका प्रभाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सत्ता-समीकरणों को भी बदल देता है।

भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। देश की लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और हर वर्ष लाखों शिक्षित युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों में सीमित अवसर, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, निजी क्षेत्र में रोजगार की अनिश्चितता और लगातार बढ़ती महंगाई ने युवाओं की अपेक्षाओं तथा वास्तविक अवसरों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है। यही बेचैनी अब देश के विभिन्न शहरों की सड़कों पर दिखाई देने लगी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार इस आंदोलन को केवल विपक्ष-प्रेरित गतिविधि या कानून-व्यवस्था की चुनौती मानकर देखती है, तो वह इसके सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने से चूक सकती है। लोकतंत्र में युवाओं की नाराज़गी का समाधान केवल प्रशासनिक एवं पुलिस सख्ती से नहीं निकलता। संवाद, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, शिक्षा सुधार और रोजगार सृजन जैसी ठोस नीतिगत पहल ही स्थायी समाधान का आधार बन सकती हैं।

फिलहाल देश की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन प्रदर्शनों को कुछ शहरों तक सीमित असंतोष मानकर आगे बढ़ेगी, या इन्हें बदलते जनमत के संकेत के रूप में पढ़ेगी। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि बड़े परिवर्तन अक्सर सड़कों से शुरू होते हैं। ऐसे में छात्र-युवा आंदोलन की दिशा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आने वाले समय की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

उत्तरी वेस्ट बैंक में आतंकी हमला, नेतन्याहू ने आईडीएफ को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

एजेंसी ■ नई दिल्ली

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी वेस्ट बैंक में हुए आतंकी हमलों के बाद सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों, उन्हें मदद पहुंचाने वालों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईडीएफ को कई कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

'द गार्जियन' की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को उत्तरी वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में चार फिलिस्तीनी और एक इजरायली सेटलर मारे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नाब्लस के पास फिलिस्तीनी गांव 'टेल' में हुई यह गंभीर घटना इस साल वेस्ट बैंक में हुआ सबसे घातक हमला है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'हम आतंक का हर जगह पीछा करेंगे। हम आतंकियों तक, उन्हें भेजने वालों तक और उनकी हर तरह से मदद करने वालों तक पहुंचेंगे और उनसे पूरा हिसाब लेंगे। पिछले दिन में हुए आतंकी हमलों के बाद, रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और मैंने सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से चर्चा के बाद आईडीएफ (इजरायली डिफेंस फोर्स) को आतंकवाद के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।'

सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित अहमदाबाद का किया दौरा, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

विश्व केसरी ■

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने बोपल, अंबली और घुमा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद दौरा किया, जहां भारी बारिश के कारण जगह-जगह पानी भर गया था।

बोपल के दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने हालात का खुद जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके में पैदल जाकर लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को राहत और पानी निकासी के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। पटेल ने सबसे पहले बोपल में जल-जमाव की स्थिति का निरीक्षण किया, जहां भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए थे। जमीनी हालात का जायजा लेते हुए, उन्होंने मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बारिश का पानी निकालने के काम और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और जरूरी मैनपावर, उपकरण और अन्य संसाधनों की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को जलजमाव की समस्या को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कोई भी रिहायशी सोसाइटी जलमग्न न रहे। बाद में, पटेल ने बारिश से प्रभावित इलाकों, अंबली और घुमा, का दौरा किया और अहमदाबाद नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, नगर आयुक्त बंछानिधि पानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश का पानी जमा होने की स्थिति का आकलन किया और अधिकारियों को भारी बारिश के कारण निवासियों को हो रही दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को प्राथमिकता दी जाए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जल-जमाव, पेड़ गिरने, सड़क धंसने और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं से संबंधित शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, एएमसी ने कहा कि भारी बारिश के दौरान उसकी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने पेड़ और टहनियां गिरने से संबंधित 166 शिकायतों पर कार्रवाई की। नगर निकाय ने बताया कि उसने पेड़ गिरने की 129 और टहनियां गिरने की 52 घटनाओं पर कार्रवाई की, साथ ही कहा कि सफाई अभियान के बाद ट्रैफिक बहाल होने के बाद शहर में कोई भी सड़क पेड़ गिरने के कारण बंद नहीं रही।

रिश्वत मामले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा

विश्व केसरी ■

गाजियाबाद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के एक मामले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की मछरा शाखा (मेरठ) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सिंघल को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला 28 अप्रैल 2016 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सिंघल ने शिकायतकर्ता से 2.50 लाख रुपए का ऋण मंजूर करने और जारी करने के बदले 28 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह ऋण 'इंदिरा संयुक्त दायित्व समूह' के लिए स्वीकृत किया जाना था, जिसका खाता उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की मछरा शाखा में था। जांच के दौरान पता चला कि बातचीत के बाद आरोपी 25 हजार रुपए रिश्वत लेने पर राजी हो गया। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और उमेश कुमार सिंघल को शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

मामले की जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 24 जून 2016 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए, जिन्हें अदालत ने स्वीकार किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने उमेश कुमार सिंघल को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें चार साल के कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

इससे पहले 23 जुलाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी अधिकारी ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय में तैनात था। सीबीआई के अनुसार इस मामले में 22 जुलाई को आरोपी अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया गया था।

डॉ. शुभदा पांडेय की साहित्य साधना: विविध आयाम पुस्तक का भव्य लोकार्पण

समाजोपयोगी लेखन नारी स्वतंत्रता का पर्याय - गिरीश पंकज

विश्व केसरी ■

आगरा । देश की सुविख्यात वरिष्ठ साहित्यकार डॉ शुभदा पांडेय के साहित्यिक जीवन पर आधारित देश के अनेक क्षेत्रों के लेखकों, शिक्षकों, विचारकों कवियों, और छात्रों द्वारा लिखित शुभकामनाएँ, संस्मरण, आलेख, समीक्षा, साक्षात्कार, कविता आदि से सुसज्जित वृहद ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। इस समारोह में बतौर अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार व संपादक गिरीश पंकज (रायपुर) , विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी(दिल्ली विश्वविद्यालय) विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर बीना शर्मा (केंद्रीय हिंदी संस्थान) आगरा ,प्रो. चित्रलेखा सिंह, (आगरा विश्वविद्यालय) ,प्रो. लक्ष्मी पांडेय(सागर विश्वविद्यालय), प्रो. कल्पना सिंह, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, एवं वरिष्ठ साहित्यकार बसंती पँवार, जोधपुर के विशिष्ट सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। पुस्तक का सम्पादन डॉ सुशील शर्मा (मिजोरम विवि) ने किया है.

अपने उद्बोधन में गिरीश पंकज ने साहित्य के विविध पहलुओं की चर्चा की और विशेष तौर पर महिला लेखन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज महिलाएँ इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अपने परिपक्व व समाजोपयोगी लेखन के साथ अपने सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का निर्धारण भी करना चाहिए क्यों कि नारी स्वतंत्रता का अर्थ किसी विकृत मानसिकता की उपज न बन सके। प्रोफेसर बीना शर्मा ने ऐसी कृतियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी पुस्तकें समाज को सारगर्भित दिशा देने में सक्षम होती हैं और शुभदा जी की साहित्यिक जीवन पर यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

लीडर्स आगरा के महासचिव सुनील जैन और सहयोगी सदस्यों ने मंचासीन सभी अतिथियों का उत्तरीय, पुष्पहार, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया । समारोह का भावपूर्ण काव्यमय संचालन कर रहे चित्तौड़गढ़ से पधारे कवि सत्तार साहब ने किया। आभार प्रकट करते हुए लीडर्स आगरा के महासचिव सुनील जैन ने कहा कि शुभदा पांडेय जी नित्य- निरंतर लेखन से जहाँ एक ओर साहित्य की संवृद्धि कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह के आयोजन से आगरा के साहित्यिक गतिविधियों को नये आयाम स्थापित कर रही हैं। इस पुस्तक की केंद्रीय साहित्यकार डॉ शुभदा पांडेय जी को लीडर्स आगरा की ओर से

शाल, स्मृति चिन्ह, गुलदस्ता आदि देकर सम्मानित किया । कुछ कवियों ने रचनाएँ सुना कर सबका दिल जीत लिया।उपस्थित लोगों में प्रो. देबाशीष गाँगुली, प्रो. जैमिनी, प्रभुदत्त उपाध्याय, राहुल कुमार, सुनील बग्गा, विजयलक्ष्मी कुलश्रेष्ठ, धर्मेंद्र सिंह, प्रो. सुषमा सिंह, राधिका गुप्ता, इंद्रावती रानी, आदि उपस्थित थे ।

तेलंगाना सरकार शहरी क्षेत्रों के प्रमुख इलाकों में इंदिराम्मा आवासों के लिए सरकारी जमीनों का उपयोग करेगी

विश्व केसरी ■

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त जमीनों का उपयोग शहरी क्षेत्रों के केंद्र में इंदिराम्मा आवासों के निर्माण के लिए करें।

इंदिराम्मा शहरी आवास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आउटर रिंग रोड (ओआरआर) सीमा के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त जमीनों की पहचान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कई विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित आवास स्थलों का विवरण दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, बैठक में इंदिराम्मा आवास योजना के लिए पुलिस, राजस्व और परिवहन विभागों के स्वामित्व वाली जमीनों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इन विभागों को अन्य स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जमीन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों से दूर इंदिराम्मा आवासों के निर्माण से निवासियों के रोजगार और आजीविका के अवसरों में कठिनाई आ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीबों के लिए निर्मित ये आवास अनुपयोगी पड़े रहते हैं। उन्होंने आवासीय क्षेत्रों के भीतर कार्यस्थलों के पास आवासों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि गरीबों की आजीविका छिन न जाए। राज्य सरकार ने पहले ही सीयूआरई क्षेत्र के अंतर्गत कई निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवासों के निर्माण की योजना की घोषणा कर दी है। प्रत्येक फ्लैट का कुल क्षेत्रफल लगभग 528 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 400 वर्ग फुट होगा। निर्माण लागत लगभग 11 लाख रुपए है, जबकि सरकार ने 5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। लाभार्थी को शेष 6 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। जमीन की पूरी लागत सरकार वहन कर रही है। पहले चरण में, 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 7,680 फ्लैटों के निर्माण और वितरण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण में, राजेंद्रनगर, महेश्वरम, सेरिलिंगमपल्ली, इब्राहिमपटनम, मल्काजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कारवां, बहादुरपुरा, अंबरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल, कुथबुल्लापुर, सनथनगर, सिकंदराबाद छावनी और मलकपेट में 'इंदिरम्मा' घर बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन विधानसभा क्षेत्रों में अप्रयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर, सड़क और भवन (आर एंड बी) विभाग के विशेष मुख्य सचिव विकास राज, डीजीपी सीवी आनंद, सीएम के प्रधान सचिव एन. श्रीधर और वी. शेषाद्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

ऑपरेशन अपराजेय के तहत दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास पर मंथन, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बनाई संयुक्त कार्ययोजना

विश्व केसरी ■

नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संचालित 'ऑपरेशन इन्विक्टस (ऑपरेशन अपराजेय)' के तहत शुक्रवार को सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण अंतरविभागीय गोष्ठी का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने की। गोष्ठी का उद्देश्य ऑटिज्म एवं बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, समुचित पुनर्वास, सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच और एक सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना रहा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में 9 जून 2026 से 'ऑपरेशन इन्विक्टस (ऑपरेशन अपराजेय)' संचालित किया जा रहा है। इस

अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं, आवश्यक सेवाओं एवं कानूनी अधिकारों से जोड़ना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक शामिल करना है। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा), जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज के सहायक प्राचार्य तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

गोष्ठी के दौरान ऑपरेशन अपराजेय की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में जनपद में दिव्यांगजनों की अनुमानित संख्या, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी (यूनीक डिसएबिलिटी आईडी) कार्ड उपलब्ध कराने, पात्र लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने, अर्ली डायग्नोसिस प्रोग्राम एवं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय एवं प्रमाणन शिविर आयोजित करने, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के अधिकाधिक नामांकन और अभिभावकों की समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पंजाब : बरनाला लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई, डीएसपी सतवीर सिंह सस्पेंड

विश्व केसरी ■

चंडीगढ़। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज और मारपीट के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसपी सतवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई घटना को लेकर बढ़ते विरोध और विभिन्न संगठनों के दबाव के बीच की गई है।

डीएसपी के निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बरनाला में सफाई कर्मचारियों के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण थी। गुरमीत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बरनाला में सफाई कर्मचारियों के साथ हुई घटना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित डीएसपी सतवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बरनाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना के विरोध में वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारी संगठनों ने पंजाब के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू कर दिए।

जालंधर में प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता दीपक तेलू ने आरोप लगाया कि बरनाला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, पर पुलिस और सिविल प्रशासन ने बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वह खुद बरनाला जाकर स्थिति का जायजा लेकर आए हैं।

दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी : प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा से बचें, ऐप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को भी अहम सलाह

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा को देखते हुए नागरिकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना जरूरी कारण यात्रा करने से बचें और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

दिल्ली पुलिस ने ऐप-आधारित मोबिलिटी एग्रीगेटर, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सलाह दी है कि वे निषेधाज्ञा लागू रहने तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का संचालन उचित तरीके से नियंत्रित करें। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कंपनियां जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों की अस्थायी जियो-फेंसिंग कर सकती हैं या फिर परिचालन की दृष्टि से संभव होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र तक आने-जाने वाली टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य ड्राइवरों, यात्रियों, डिलीवरी पार्टनरों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही कम कर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना है।

जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने तीन और आरोपियों को किया गिरफ्तार

विश्व केसरी ■

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी ने शुक्रवार को तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

सीआईडी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए रांची के दो होटलों में भी छापेमारी की है। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) विभिन्न डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच कर रहा है। सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा संचालन से जुड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के कर्मचारी हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के अनुसार, तीनों से परीक्षा संचालन और डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सीआईडी ने जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी तथा कंपनी के कर्मचारी मो. उस्मान और मो. एबाद को गिरफ्तार किया था।

अदालत के आदेश पर इन पांचों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, रांची पुलिस के सहयोग से शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में स्थित दो होटलों में भी छापेमारी की गई है। हालांकि, वहां से क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। इस पूरे मामले में सीआईडी थाना में कांड संख्या 16/2026 दर्ज की गई है। जांच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत की जा रही है।

जांच के दौरान सीआईडी ने जेपीएससी मुख्यालय और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालयों में छापेमारी कर सर्वर, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित कई डिजिटल उपकरण और परीक्षा संबंधी दस्तावेज जब्त किए हैं।

2 करोड़ की मांग को हाईकोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता

10 लाख के गुजारा भत्ते का फैसला बरकरार

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि मध्यस्थता के दौरान 2 करोड़ रुपए जैसी अत्यधिक आर्थिक मांग करना, यदि वैवाहिक समझौते में बाधा बनता है, तो परिस्थितियों के अनुसार इसे पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें महिला के लिए 10 लाख रुपए का एकमुश्त स्थायी भरण–पोषण तय किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

मामला रायपुर के एक दंपती से जुड़ा है, जिनका विवाह 29 जून 2020 को हुआ था। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और वे अलग रहने लगे। पति ने फैमिली कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि 7 फरवरी 2022 को पत्नी अपने भाई की शादी में जाने के बहाने मायके चली गई और लगभग 35 लाख रुपए मूल्य के पुश्तैनी आभूषण तथा अन्य कीमती सामान अपने साथ ले गई। पति का यह भी कहना था कि महिला थाना और सखी सेंटर में काउंसलिंग के बावजूद पत्नी वापस नहीं लौटी। इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका दायर की।

फैमिली कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?

फैमिली कोर्ट ने पति की आय, पत्नी की शैक्षणिक योग्यता और मामले के तथ्यों को देखते हुए पत्नी के लिए 10 लाख रुपए का एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित किया था। इस आदेश से असंतुष्ट पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर गुजारा भत्ते की राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की मांग की।

मध्यस्थता में 2 करोड़ की मांग पर क्या कहा हाईकोर्ट?

हाईकोर्ट ने 18 जून 2026 को दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेजा था, ताकि आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो सके। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मध्यस्थता के दौरान पत्नी ने एकमुश्त 2 करोड़ रुपए की मांग रखी। पति ने अपनी आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक खातों का हवाला देते हुए इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद समझौता नहीं हो सका। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यदि अत्यधिक और असामान्य आर्थिक मांग के कारण मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो यह इस बात का संकेत है कि वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं। ऐसे में विवाह को जबरन बनाए रखना पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

पुलिस मामलों पर भी अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अलग रहने के दौरान पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। साथ ही मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कथित फर्जी प्रोफाइल बनाने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई। फैसले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा कि इन परिस्थितियों को पति और उसके परिवार को प्रताड़ित एवं अपमानित करने के प्रयास के रूप में देखा गया। अदालत ने यह भी नोट किया कि पति और उसके परिजनों के प्रयासों के बावजूद पत्नी ने साथ रहने से लगातार इनकार किया।

पुलिस के आश्वासन के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन स्थगित

विश्व केसरी

रायपुर। राजीव भवन (कांग्रेस मुख्यालय) पर भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले और उसके बाद कांग्रेस नेताओं पर दर्ज गैर–जमानती धाराओं के खिलाफ चल रहा अनिश्चितकालीन धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जंतर–मंतर पर राहुल गांधी को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के विरोध से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद छत्तीसगढ़ में उग्र रूप ले चुका है। राजीव भवन (कांग्रेस मुख्यालय) पर भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले और उसके बाद कांग्रेस नेताओं पर दर्ज गैर–जमानती धाराओं के खिलाफ चल रहा अनिश्चितकालीन धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

रायपुर के खम्हारडीह थाने के सामने रातभर चले इस आंदोलन के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक हुई। पुलिस द्वारा लिखित में सभी मांगें मानने और दोषी भाजपा कार्यकर्ताओं पर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदर्शन को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का ऐलान किया।

कांग्रेस की 3 प्रमुख मांगें जिन पर बनी सहमति

भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर: राजीव भवन (कांग्रेस भवन) पर हमला करने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर काउंटर FIR दर्ज की जाए।

घायलों का मेडिकल परीक्षण: बीजेपी हमले में घायल हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डॉक्टरी मुलाहिजा कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

गैर–जमानती धाराओं की समीक्षा: कांग्रेस के 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगाई गई गंभीर गैर–जमानती धाराओं की विवेचना कर उन्हें हटाया जाए।

आंदोलन के दौरान खम्हारडीह थाने के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता रातभर थाने के बाहर जमे रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का–मुक्की भी हुई। शुक्रवार सुबह हुई उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस की ओर से मध्य जोन DCP तारकेश्वर पटेल, नॉर्थ जोन DCP दीपमाला कश्यप, ADCP आदित्य पांडे और ACP पूर्णिमा लांबा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से दीपक बैज, सह प्रभारी जरिता लैतफलांग, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, सुशील आनंद शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा शामिल हुए। राजनीति

दीपक बैज का तीखा हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैज ने कहा, 'हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। बीजेपी की यह कार्रवाई पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।'

भूपेश बघेल की चेतावनी: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित हमला किया गया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि 'भाजपा सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है, इसलिए अधिकारी निष्पक्ष काम करें।'

संक्षिप्त खबरें

पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन द्वारा विशेष बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

विश्व केसरी

रायपुर। पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के तत्वावधान में आज श्रृष्टि स्पेशल स्कूल, डंगनिया, रायपुर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी) वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए म्यूचुअल फंड जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों एवं उनके परिवारों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना तथा भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. उदय भान सिंह चौहान ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय योजना एवं सुरक्षित निवेश अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विशेष बच्चों के अभिभावकों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमित बचत एवं सुनियोजित निवेश अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक सौरभ साहू ने सरल एवं प्रभावी प्रस्तुति के माध्यम से म्यूचुअल फंड, व्यवस्थित निवेश योजना, दीर्घकालीन निवेश, जोखिम प्रबंधन तथा आर्थिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

अतिथि शिक्षकों की हड़ताल स्थगित

विश्व केसरी

रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने फिलहाल आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया। हालांकि शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि यदि 5 सितंबर 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे दोबारा प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। दुर्ग में आयोजित प्रेसवार्ता में अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पढ़ाई बाधित करना नहीं था, लेकिन वर्षों से मानदेय और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2016 से तय मानदेय आज की महंगाई के हिसाब से बेहद कम है। कई अतिथि शिक्षक दूर–दराज़ और नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिल रहा।

मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगें

अतिथि शिक्षकों ने बताया कि नियमित शिक्षकों और उनके मानदेय में बड़ा अंतर है। उनका कहना है कि जहां नियमित शिक्षकों को करीब 1 लाख रुपये तक वेतन मिलता है और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को लगभग 38 हजार रुपये मासिक मिलते हैं, वहीं अतिथि शिक्षकों को केवल 20 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है।

आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च

विश्व केसरी

रायपुर। नीट पेपर लीक मामले में 30 बच्चों द्वारा अब तक आत्महत्या करने पर आम आदमी पार्टी पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन कर शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर तक कैंडल मार्च निकाला गया।आप नेताओं ने बताया कि पिछले 10 बरसों में 89 बार प्रश्नपत्र लीक हुए–48 बार परीक्षा दोबारा हुई। हर बार वही वादे, और फिर वही चुप्पी। NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के सदमे के कारण देशभर में 30 छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के दुखद है। इस घटनाक्रम ने छात्रों और उनके परिवारों के बीच भारी मानसिक तनाव और आक्रोश पैदा कर दिया है। इन सभी मामलों में छात्र परीक्षा रद्द होने और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण वह अत्यधिक तनाव में थे जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया और इस सबके लिए जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आप नेताओं के कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 50 दिनों से युवा आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस की लाठी डंडे खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यह सरकार सोई हुई है। मोदी सरकार देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दें, सरकार बच्चों के परिवार को मुआवजा दे।

जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर सुकमा में कांग्रेस का प्रदर्शन

विश्व केसरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में जिलेभर से पहुंचे आदिवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता सुकमा बस स्टैंड पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले बड़े नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कर रही है, जबकि वर्षों से जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

जिला मुख्यालय में जुटे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी

सुकमा बस स्टैंड पर आयोजित प्रदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी, कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर उनकी रिहाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने इस मुद्दे पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

हरीश कवासी ने सरकार से उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है, उन्हें सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। ऐसे में लंबे समय से जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों पर भी संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं या जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं, उनके प्रकरणों की समीक्षा कर न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विक्रम मंडावी ने भी किया समर्थन

प्रदर्शन में शामिल बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने भी सरकार से आदिवासी बंदियों के मामलों की समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और उनके लिए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ना कठिन हो गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जार रहेगा।

वन्य जीव संरक्षण का अनोखा संगम है नंदन–जंगल सफारी

विश्व केसरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर–39 में स्थित नंदनवन जंगल सफारी राज्य के प्रमुख पर्यटन और भूमि संरक्षण आरक्षण में शामिल है। 320.15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला विशाल यह परिसर प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और ज्वालामुखी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रासंगिक संरक्षण के साथ–साथ प्राकृतिक वातावरण में नमूनों को देखने और उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है।

मिनी जू से जंगल जापान तक का सफर

नंदनवन की शुरुआत वर्ष 1979 में रायपुर में 'नंदनवन मिनी जू' के रूप में हुई थी। यह सामान के सामान और राहत केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। वर्ष 2008 में सेंट्रल जू अथॉरिटी (सीजेडए) ने इसे आधिकारिक रूप से 'मिनी जू' की परिभाषा दी।

इसके बाद नवा रायपुर में आधुनिक और विशाल जंगल तीरंदाजी विकसित करने के लिए वर्ष 2012 से 2015 के बीच 320.15 हेक्टेयर भूमि की पेशकश की गई। 1 नवंबर 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नंदनवन जंगल सफारी का उद्घाटन किया।

प्राकृतिक पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षा पर विशेष जोर

नंदनवन जंगल सचित्र का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यहां सामानों को उनके प्राकृतिक वातावरण के ढांचे, सुरक्षित और तनावमुक्त आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। छात्रों और वस्तुओं को पर्यावरण के नमूने और जैव विविधता के महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहां विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

पांच प्रमुख सावन जोन हैं आकर्षण का केंद्र

नंदनवन जंगल सचित्रों को सादृश्यों की सुरक्षा और दृश्य सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए अलग–अलग जोन में विकास किया गया है। 30.89 हेक्टेयर क्षेत्र में इस क्षेत्र में चीतल, सांभर, नीलगाय और काला हिरण जैसे प्राकृतिक वातावरण का विचरण करते 20.03 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित भालू चित्र प्रदर्शनी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां भालुओं को प्राकृतिक वातावरण में देखने का मौका मिलता है।

जटिल सर्जरी से खुला मुंह, आयुष्मान योजना से मिला नि:शुल्क उपचार

विश्व केसरी

रायपुर। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध सिम्स अस्पताल, बिलासपुर के दंत चिकित्सा विभाग ने एक दुर्लभ एवं जटिल शल्य चिकित्सा कर 24 वर्षीय युवक के बचपन से बंद जबड़े को सफलतापूर्वक खोलने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अविकसित निचले जबड़े के कारण वर्षों से सामान्य रूप से मुंह नहीं खोल पाने वाले मरीज का आधुनिक तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसे नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया।

मुंगेली जिले के अमली कापा निवासी 24 वर्षीय युवक बचपन में लगी चोट के कारण बाइलेटरल टेम्पोरो–मैंडिबुलर जॉइंट (क्ररुञ्जरुछ्व) एंकिलोसिस से पीड़ित था। इस बीमारी के कारण उसके जबड़े की वृद्धि रुक गई थी और वह वर्षों से केवल तरल आहार ही ले पाता था। पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से वह कुपोषण और शारीरिक दुर्बलता का भी शिकार हो गया था। निजी अस्पतालों में उपचार का अनुमानित खर्च 3 लाख रुपये से अधिक होने के कारण वह इलाज नहीं करा सका। बाद में सिम्स पहुंचने पर उसे आयुष्मान योजना के तहत नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिली। दंत चिकित्सा विभाग में मरीज की विस्तृत जांच, रक्त परीक्षण, सीबीसीटी एवं अन्य रेडियोलॉजिकल जांच के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई। चूंकि मरीज का मुंह पूरी तरह बंद था, इसलिए निश्चेतना देने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी कर श्वास नली स्थापित की गई। इसके बाद 4 जून 2026 को लगभग छह से सात घंटे तक चली जटिल सर्जरी में डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस तकनीक का उपयोग कर अविकसित निचले जबड़े को लंबा करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

शासकीय अस्पताल कोनी को मिली अत्याधुनिक ब्लड सेंटर संचालन की अनुमति

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। कुमार साहब स्व. दिलीप सिंह जूदेव शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कोनी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अत्याधुनिक ब्लड सेंटर के संचालन के लिए आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त हो गया है। यह महत्पपूर्ण उपलब्धि जिला प्रशासन, औषधि एवं खाद्य नियंत्रक विभाग के सतत सहयोग एवं मागदर्शन से प्राप्त हुई है।

अस्पताल में स्थापित यह अत्याधुनिक ब्लड सेंटर एनटीपीसी सीपत द्वारा सीएसआर मद के अंतर्गत निर्मित किया गया है। आधुनिक उपकरणों और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार यह रक्त केंद्र प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सबसे उन्नत ब्लड सेंटर के रूप में स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना एवं विकास में संचालक प्राध्यापक सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. भानु प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा ब्लड बैंक के क्षेत्र में उनके 25 वर्षों के अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस ब्लड सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पहला ऐसा केंद्र बनेगा, जहां सिंगल डोनर प्लेटलेट तैयार करने और मरीजों को उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा डेंगू, कैंसर, बोन मैरो प्रत्यारोपण, थैलेसीमिया और गंभीर रक्त विकारों से पीड़ित मरीजों के उपचार में अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इससे मरीजों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाली प्लेटलेट्स उपलब्ध हो सकेंगी और निजी संस्थानों पर उनकी निर्भरता कम होगी। अधीक्षक डॉ. भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इस ब्लड सेंटर का उद्देश्य केवल सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त और रक्त अवयव उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि प्रदेश के मरीजों को विश्वस्तरीय ट्रांसफ्यूजन सेवाएं प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में एसडीपी सुविधा की शुरुआत शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अस्पताल प्रशासन ने इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर, औषधि एवं खाद्य नियंत्रक विभाग, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन तथा एनटीपीसी सीपत का आभार व्यक्त किया है। अस्पताल का मानना है कि यह अत्याधुनिक ब्लड सेंटर न केवल बिलासपुर संभाग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के गंभीर मरीजों के लिए जीवनरक्षक सुविधा सिद्ध होगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेगा।

टिकट चेकिंग के दौरान 212 मामलों में 1,53,765 रुपए राजस्व की प्राप्ति

विश्व केसरी

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ सुस्कर विपुल विलासराव के निर्देश पर भाटापारा रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान दिनांक 23 जुलाई, 2026 को चलाया गया। जिसमें भाटापारा स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, 08 ट्रेनों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान में कुल 212 मामलों को दर्ज कर 1,53,765 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया।

किलाबंदी टिकट चेकिंग में बिना टिकट यात्रा करने वाले 110 यात्री पकड़े गए, जिससे 98,665/– राजस्व प्राप्त हुआ। अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 66 यात्रियों से 51500/– रूपये राजस्व प्राप्त हुआ, अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले 36 यात्रियों से 3600/– रूपये राजस्व प्राप्त हुआ । इस टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करना था । इस टिकट चेकिंग अभियान का संचालन सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद के द्वारा एवं मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक ए. जेना, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक–टिकट चेकिंग अविजित डे सहित 12 टिकट चेकिंग स्टाफ, 04 आरपीएफ स्टाफ शामिल रहे । रेल प्रशासन यात्रियों को आगाह करता है कि वे यात्रा हेतु उचित टिकट एवं रेल परिसर मे प्रवेश करने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें।

संपादकीय

संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र, हिंसा से नहीं

ललित गर्ग

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक हाल के आंदोलन के दौरान जो तनाव, टकराव और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं, वे केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास, मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिश, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग-ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं कहे जा सकते, जिसकी आधारशिला अहिंसा, संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं पर रखी गई है। भारत आज आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। यदि हम आज भी असहमति को हिंसा, टकराव और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति सड़क पर शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, बल्कि

विचारों की शक्ति, संवाद की संस्कृति और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निहित होती है। भारतीयवायु सेना भर्ती

राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर चल रहे घरना-प्रदर्शन के दौरान अचानक अपने सहयोगी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठना और संसद की बजाय सड़क को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने संसद चलो मार्च के दौरान तनावपूर्ण, अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएं सामने आईं, उससे यह आशंका बलवती हुई कि कुछ राजनीतिक शक्तियां भारत में भी नेपाल जैसी अराजक परिस्थितियां पैदा करने को उजावले हैं। सरकार की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गई कार्रवाई से, कुछ कमियों के बावजूद, इस बड़े संकट को टाल दिया गया, अन्यथा दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और अशांति की चपेट में आ सकती थी। देश पहले भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग में लगभग सौ दिनों तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने और उससे आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाइयों का अनुभव कर चुका है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद, संवाद और संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि सड़क पर टकराव और अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करना है या राजनीतिक ध्रूवीकरण और अस्थिरता को बढ़ावा देना। जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी जुड़ी होती है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम नागरिकों के जीवन को बाधित करना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। यदि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो उसकी मांगें भी समाज की सहानुभूति खो बैठती हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी उत्तरदायित्व का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखना चाहिए। जब भी किसी वर्ग, विशेषकर युवाओं और छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो, तो उसका समय रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे, टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है।

इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका उदाहरण है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आंदोलन का नैतिक बल उसकी शांति और अनुशासन में था।

नीट के बवाल के बीच एक बड़ा सवाल: डॉक्टर बनने की राह में संवेदनाएँ कहाँ खो जाती हैं?

डॉ. सत्यवान सौरभ

देश में जब भी नीट (NEET) परीक्षा होती है, उसके बाद केवल परिणामों की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की चर्चा शुरू हो जाती है। कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा की पारदर्शिता, कभी आरक्षण, कभी कट-ऑफ और कभी लाखों विद्यार्थियों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर बहस छिड़ जाती है। हर वर्ष करोड़ों सपनों का भार इस एक परीक्षा पर टिका होता है। माता-पिता अपनी वर्षों की बचत दाँव पर लगा देते हैं, विद्यार्थी दिन-रात एक कर देते हैं और समाज उन सफल अभ्यर्थियों को भविष्य का जीवनरक्षक मानकर गर्व महसूस करता है।

लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक ऐसा प्रश्न है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी सबसे कम पूछा जाता है। आखिर यही बच्चे, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करते हैं, उनमें से कुछ आगे चलकर ऐसे डॉक्टर क्यों बन जाते हैं जिनके व्यवहार को लेकर समाज में असंतोष दिखाई देता है? क्यों कभी-कभी मरीज को लगता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति पहले डॉक्टर नहीं, बल्कि एक व्यवसायी है? यह प्रश्न किसी पूरे चिकित्सक समुदाय पर आरोप नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल है जो एक संवेदनशील विद्यार्थी को कभी-कभी संवेदनहीन पेशेवर में बदल देती है।

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश के अधिकांश डॉक्टर आज भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और करुणा के साथ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि हजारों चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच कार्य करने वाले डॉक्टर आज भी चिकित्सा सेवा की गरिमा बनाए हुए हैं। इसलिए कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर पूरे चिकित्सक समुदाय का मूल्यांकन करना अन्याय होगा। लेकिन यदि समाज में डॉक्टरों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, तो उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना भी उतना ही आवश्यक है।

समस्या की शुरुआत मेडिकल कॉलेज से भी पहले हो जाती है। आज डॉक्टर बनने की तैयारी एक प्रतियोगी उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को सफलता का अर्थ केवल रैंक, अंक और सीट समझाया जाता है। चिकित्सा को सेवा नहीं, बल्कि उपलब्धि और प्रतिष्ठा का माध्यम मानने की मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होने लगती है। जब लक्ष्य केवल किसी भी कीमत पर मेडिकल सीट प्राप्त करना रह जाए, तब संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों की चर्चा पीछे छूट जाती है।

इसके बाद यदि कोई छात्र अत्यधिक महँगे निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहाँ शिक्षा पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक खर्च होते हैं, तो आर्थिक दबाव भी उसके भविष्य को प्रभावित करता है। कई परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह भावना जन्म लेती है कि अब इस निवेश की भरपाई करनी है। यह सोच चिकित्सा की मूल भावना के विपरीत है, लेकिन शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने इस मानसिकता को कहीं न कहीं जन्म दिया है।

मेडिकल शिक्षा स्वयं भी अत्यंत कठिन है। वर्षों तक लगातार अध्ययन, इंटर्नशिप की लंबी ड्यूटी,

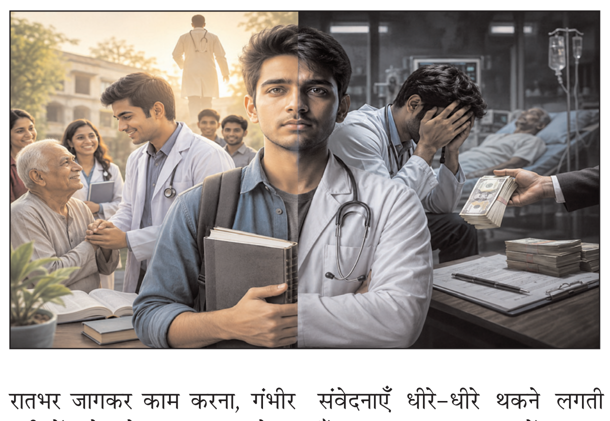

रातभर जागकर काम करना, गंभीर मरीजों से रोज़ सामना होना, मानसिक तनाव और कई बार कठोर प्रशिक्षण—यह सब एक युवा छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान उसे भावनात्मक सहयोग, नैतिक चिकित्सा और मानवीय व्यवहार का पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले, तो धीरे-धीरे मरीज एक इंसान नहीं, बल्कि एक 'केस' बनकर रह जाता है।

सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। एक-एक डॉक्टर को सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं। सीमित संसाधनों, दवाओं की कमी और प्रशासनिक दबाव के बीच हर मरीज को पर्याप्त समय देना कई बार संभव नहीं होता। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में कई स्थानों पर आय, पैकेज और लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति का दबाव रहता है। ऐसे माहौल में चिकित्सा सेवा और व्यापार के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है।

समस्या केवल डॉक्टरों की भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ढाँचा कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है जहाँ मानवीय संवेदनाएँ धीरे-धीरे थकने लगती हैं। लगातार तनाव, मुकदमों का डर, हिंसा की घटनाएँ, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के आरोप और हर परिस्थिति में चमत्कार की अपेक्षा—ये सभी बातें डॉक्टरों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालती हैं। जब समाज और व्यवस्था दोनों किसी पेशे को लगातार तनाव में रखें, तो उसका असर व्यवहार पर पड़ना स्वाभाविक है।

इसके बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि कुछ डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक जाँचें लिखना, कमीशन आधारित रेफरल देना, अत्यधिक शुल्क लेना या मरीज के साथ असम्मानजनक व्यवहार करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चिकित्सा केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि विश्वास का भी पेशा है। एक बार यदि यह विश्वास टूटता है तो उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है।

सबसे बड़ी कमी शायद हमारी चिकित्सा शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण की है। मेडिकल विद्यार्थियों को शरीर की संरचना, रोगों की पहचान और आधुनिक उपचार पद्धतियाँ तो विस्तार से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन करुणा, संवाद, सहानुभूति और चिकित्सा नैतिकता को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए। जबकि मरीज को सबसे पहले दवा नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। कई बार डॉक्टर का एक मधुर शब्द भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।

नीट पर होने वाली बहस केवल परीक्षा की निष्पक्षता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो मेडिकल शिक्षा को केवल ज्ञान और तकनीक तक सीमित रखने के बजाय उसे मानवीय मूल्यों से भी जोड़ना होगा। मेडिकल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, संवाद कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि चिकित्सा केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है।

सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, निजी मेडिकल शिक्षा की फीस को अधिक न्यायसंगत बनाने, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जब व्यवस्था ही संतुलित होगी, तभी उससे निकलने वाले पेशेवर भी अधिक संतुलित होंगे।

समाज को भी आत्ममंथन करना चाहिए। डॉक्टर से चमत्कार की अपेक्षा करना, छोटी-सी असफलता पर हिंसा करना या बिना तथ्यों के पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर और मरीज का संबंध विश्वास पर आधारित होता है और इस विश्वास की रक्षा दोनों पक्षों को मिलकर करनी होगी।

नीट की निष्पक्षता आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला प्रत्येक डॉक्टर केवल सफल परीक्षार्थी न हो, बल्कि संवेदनशील इंसान भी हो। देश को ऐसे चिकित्सकों की आवश्यकता है जिनके हाथों में विज्ञान की दक्षता हो, मस्तिष्क में ज्ञान हो और हृदय में करुणा। क्योंकि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे पवित्र सेवाओं में से एक है।

नीट के विवादों के बीच यदि हम इस बड़े प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार कर सकें कि डॉक्टर बनने की यात्रा में संवेदनाएँ क्यों कमजोर पड़ जाती हैं, तो शायद भविष्य में हमें केवल उत्कृष्ट चिकित्सक ही नहीं, बल्कि ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे जिन पर मरीज बिना किसी भय और संदेह के अपना जीवन सौंप सकें।

कांग्रेस की वापसी: क्या भारतीय राजनीति में फिर बदल रहा है समीकरण?

सुजीत कुमार

भारतीय राजनीति में एक कहावत लंबे समय से प्रचलित है— 'कांग्रेस को कभी खत्म मत मानिए।' आजादी के बाद देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति रही कांग्रेस कई बार ऐसे दौर से गुजरी जब उसके राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठे। लेकिन हर बड़े संकट के बाद उसने खुद को फिर से खड़ा किया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की तुलना उस पौराणिक पक्षी 'फीनिक्स' से करते हैं, जो राख से दोबारा जन्म लेता है।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर भाजपा के पूर्ण वर्चस्व वाली राजनीति को पहली बार गंभीर चुनौती दी। इसके बाद कई राज्यों में संगठन की सक्रियता, विपक्षी दलों के साथ बेहतर तालमेल और केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष ने कांग्रेस को नई राजनीतिक ऊर्जा दी है। विपक्षी राजनीति का केंद्र भी तेजी से कांग्रेस के इर्द-गिर्द सिमटता दिखाई दे रहा है।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस को कमज़ोर आँकना अक्सर राजनीतिक भूल साबित हुआ है। वर्ष 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस केवल 154 सीटों पर सिमट गई थी और पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। उस समय माना गया कि पार्टी का युग समाप्त हो गया है। लेकिन मात्र तीन वर्ष बाद 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 353 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सत्ता में लौट आई।

1989 में बोफोर्स विवाद के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसके बावजूद 1991 के आम चुनाव में, राजीव गांधी की हत्या जैसी असाधारण परिस्थितियों के बीच भी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसी सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी।

1996 और 1998 के बीच कांग्रेस का संगठन बिखरता नजर आया। लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने खुद को पुनर्गठित किया। नतीजा 2004 में सामने आया, जब लगभग सभी राजनीतिक आकलनों को गलत साबित करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने केंद्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 2009 में कांग्रेस ने 206 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई।

2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस क्रमशः 44 और 52 सीटों तक सिमट गई। तब एक बार फिर यह धारणा बनी कि राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। लेकिन 2024 में पार्टी ने 99 सीटें जीतकर न केवल उल्लेखनीय वापसी की, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की धुरी के रूप में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

इस पुनरुत्थान के पीछे राहुल गांधी की बदली हुई राजनीतिक भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने अधिक परिपक्व, लगातार सक्रिय और संघर्षशील विपक्षी नेता की छवि बनाई है। संसद से लेकर सड़कों तक सरकार को लगातार चुनौती देना, लंबी जन यात्राएं, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर आक्रामक अभियान और विपक्षी दलों को साथ लाने के प्रयासों ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया है।

विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती और सामाजिक असंतोष जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बने रहते हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट का रुझान जारी रहता है, तो उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि कांग्रेस के सामने संगठन को राज्यों में मजबूत करने, क्षेत्रीय दलों के साथ संतुलन बनाने और चुनावी बढ़त को वोटों में बदलने जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं।

भारतीय राजनीति का इतिहास एक बार फिर यही याद दिला रहा है कि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से समाप्त घोषित करना या समझना शायद सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है।

बोधकथा

आत्मचिंतन :- आखिर में यह भी नहीं रहेगा

एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वह एक गाँव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधू की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधू को विदा किया।

साधू ने आनंद के लिए प्रार्थना की – 'भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे।' साधू की बात सुनकर आनंद हँस पड़ा और बोला – 'अरे, महात्मा जी! जो है यह भी नहीं रहने वाला।' साधू आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया।

दो वर्ष बाद साधू फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गाँव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधू आनंद से मिलने गया।

आनंद ने अभाव में भी साधू का स्वागत किया। झोंपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया। खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधू की आँखों में आँसू थे। साधू कहने लगा – 'हे भगवान् ! ये तूने क्या किया?

आनंद पुनः हँस पड़ा और बोला – 'महाराज आप क्यों दुःखी हो रहे है? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान् इन्सान को जिस हाल में रखे, इन्सान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है ।

तीर तेवर

सागर कुमार

व्यंग्य केसरी

धूर्तता एक कला !

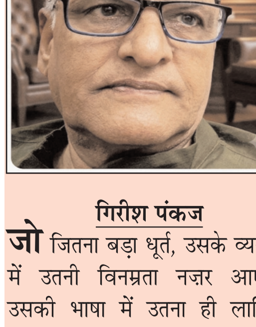

गिरीश पंकज

जो जितना बड़ा धूर्त, उसके व्यवहार में उतनी विनम्रता नज़र आएगी। उसकी भाषा में उतना ही लालित्य होगा । लोग चकित हो जाएंगे, अरे! यह कितना महान व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही लोग उनसे रू-ब-रू मिलेंगे, सारा भ्रम जाता रहेगा। इस अकाट्य सत्य को अगर आज के कॉर्पोरेट और सोशल मीडिया के दौर में देखें, तो यह धूर्तता एक बकायदा 'कला' का रूप ले चुकी है। ?आजकल बाज़ार में 'सच्चाई' का भाव टमाटर से भी सस्ता चल रहा है, और 'विनम्रता' का भाव आसमान छू रहा है। नियम बड़ा सीधा है—भीतर जितना बड़ा खोखलापन होगा, बाहर उतनी ही चमकीली पैकेजिंग होगी।

?एक सज्जन हैं। नाम है उनका, श्रीमान विनीत कपटी। ? विनीत नाम तो अच्छा है लेकिन बाद में उनके आचरण को देखकर लोगों ने उन्हें कपटी कहना शुरू कर दिया। विनीत जी जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं या मंच से बोलते हैं, तो उनकी भाषा में इतना लालित्य, इतना रस और इतनी शालीनता होती है कि सुनने वाले को लगता है साक्षात् सरस्वती जी उनके कंठ में आकर बैठ गई हैं। उनकी हर दूसरी लाइन में सादर प्रणाम...आपका अनुज और वसुधैव कुटुंबकम् जैसे शब्द ऐसे तैरते हैं, जैसे चाशनी में डूबा रसगुल्ला। लोग भावुक होकर कहते हैं, 'अहा!कलयुग में साक्षात देवता अवतरित हुए हैं ।'

?उनकी इस अतिशय विनम्रता और 'लल्लो-चप्पो' भाषा से सम्मोहित होकर एक दिन हमारे सीधे-साधे शर्मा जी उनसे 'रू-ब-रू' मिलने पहुँच गए। शर्मा जी को लगा था कि वहां जाते ही विनीत जी बोल उठेंगे,

'अरे वाह शर्मा जी!आपकी आने से मेरी कुटिया पावन हो गई!' लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ?।शर्मा जी जैसे ही कपटी जी के आलीशान दफ्तर के केबिन में घुसे, सारा लालित्य धुआं हो गया। ?मंच पर 'परहित सरिस धरम नहिं भाई' का पाठ पढ़ाने वाले विनीत जी, असल जिंदगी में अपने चपरासी पर चिल्ला रहे थे, 'अबे गधे की दुम!चाय में चीनी कम है,तेरी सैलरी से कटूँगा ।

?शर्मा जी को देखते ही उनके चेहरे की वह 'दिव्य मुस्कान' ऐसे गायब हुई, जैसे पुलिस को देखकर जेबकतरा गायब होता है । कपटी जी ने शर्मा जी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और बेहद रूखे स्वर में बोले, 'जल्दी फरमाइए, क्या काम है? मुझे कहीं निकलना है!'

?शर्मा जी का मुँह खुला-का-खुला रह गया। उनका वो 'महान व्यक्ति' वाला भ्रम चंद सेकेंडों में वैसे ही टूट गया जैसे शीशे का गिलास पत्थर से टकराकर टूटता है।

लौटते वक़्त शर्माजी सोच रहे थे, अतिशय विनम्रता और भाषा का लालित्य एक प्रकार का 'सुरक्षा कवच' है। धूर्त लोग जानते हैं कि अगर वो सीधे बात करेंगे, तो उनका असली चेहरा,जो कि काफी बदसूरत है, तुरंत दिख जाएगा। इसलिए वे शब्दों का ऐसा इत्र छिड़कते हैं कि सामने वाले को उनकी भीतरी दुर्गंध का अहसास ही न हो। ?इसलिए हुजूर, अगली बार जब कोई आपसे ज़रूरत से ज़्यादा झुककर बात करे, उसकी भाषा में शहद से ज़्यादा मिठास हो, और वह बात-बात पर खुद को आपका 'दास' बताए... तो समझ लीजिएगा कि जेब कटने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ा चूना लगने वाला है!

मो. 9425212720

इतिहास

24 जुलाई के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से माचू पिचाकू की खोज, लुसाने की संधि और हेले-बॉप धूमकेतु की खोज शामिल हैं.प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं1911: अमेरिकी खोजकर्ता हीरम बिंघम ने पेरू में स्थित प्राचीन इनका शहर माचू पिच्चू (Machu Picchu) की फिर से खोज की.1923: तुर्की और प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों के बीच लुसाने की संधि (Treaty of Lausanne) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे आधुनिक तुर्की की सीमाओं का निर्धारण हुआ.1995: खगोलविद एलन हेल और थॉमस बॉप ने 20वीं सदी के सबसे अधिक देखे जाने वाले धूमकेतुओं में से एक हेले-बॉप धूमकेतु (Hale-Bopp) की स्वतंत्र रूप से खोज की.2013: स्पेन के सैंटियागो डी कंपोस्टेला में एक भीषण हाई-स्पीड ट्रेन दुर्घटना में 79 लोगों की मौत हो गई ।

तीन साल बाद भी हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं, चिकित्सा शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस

नर्सिंग कॉलेजों की नियमित भर्ती का मामला; हाईकोर्ट ने 2023 में 100% महिला आरक्षण के प्रावधान को किया था असंवैधानिक

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कटारिया (IAS) को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 9 मार्च 2023 को पारित स्नक्र निर्णय का अब तक विधि के अनुरूप अनुपालन नहीं किया गया। अवमानना याचिका अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ. अजय त्रिपाठी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना, आशुतोष मिश्रा एवं रूपेश साहू ने प्रस्तुत की है।

हाईकोर्ट ने निरस्त किया था 100 प्रतिशत महिला आरक्षण

मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है। याचिकाकर्ताओं ने WPS क्रमांक 7183/2021 एवं संबद्ध याचिका के माध्यम से छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची-III के नोट-2 तथा 8 दिसंबर 2021 की भर्ती विज्ञप्ति के क्लॉज-5 को चुनौती दी थी। 9 मार्च 2023 को डिवीजन बेंच ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने माना था कि शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर एवं सहायक प्राध्यापक की सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप नहीं है।

सीजीपीएससी ने मांगा था संशोधित अधियाचन

अवमानना याचिका में कहा गया है कि फैसले के महज कुछ दिनों बाद 15 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी दी थी। आयोग ने निर्णय के अनुरूप संशोधित अधियाचन भेजने का अनुरोध भी किया था, ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इसके बावजूद विभाग ने न तो भर्ती नियमों में अपेक्षित संशोधन किया और न ही नियमित भर्ती आगे बढ़ाने के लिए संशोधित अधियाचन आयोग को भेजा।

नियमित भर्ती के बजाय संविदा विज्ञापन जारी करने का आरोप

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुराने निर्णय के अनुपालन की प्रतीक्षा के बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 22 जून 2026 को संविदा भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया। इसके खिलाफ भी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बाद की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से 15 मार्च 2023 के CGPSC पत्र का उल्लेख किए जाने को अवमानना याचिकाकर्ताओं ने इस बात के समर्थन में रखा है कि विभाग को वर्ष 2023 के न्यायालयीन निर्णय की जानकारी थी।

सचिव अमित कटारिया से मांगा जवाब

याचिकाकर्ताओं ने इसे न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय की जानबूझकर एवं सविचारित अवज्ञा (Wilful and Deliberate Disobedience) बताते हुए अवमानना कार्रवाई की मांग की है। 23 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की पीठ ने अवमानना याचिका पर प्रतिवादी क्रमांक-1, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कटारिया को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अब मामले में सचिव की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।

सूरजपुर में भड़का जमीन विवाद, पथराव में डीएसपी समेत 24 पुलिसकर्मी घायल

विश्व केसरी

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को हिंसक हो गया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदननगर-धरमपुर गांव में कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया। इस घटना में डीएसपी राजेश जोशी समेत 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

क्या है पूरा मामला?

मदननगर-धरमपुर क्षेत्र में एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नकद मुआवजा स्वीकार नहीं है। उनकी मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए। इसी मांग को लेकर वे लगातार विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रशासन की सर्वे टीम गांव पहुंची थी। आरोप है कि उस दौरान ग्रामीणों ने सर्वे दल को बंधक बना लिया था। इसी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम भारी सुरक्षा बल के साथ गांव पहुंची थी।

कार्रवाई के दौरान भड़का विवाद

पुलिस टीम के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव में डीएसपी राजेश जोशी सहित 24 से अधिक पुलिसकर्मियों के सिर और शरीर पर चोटें आईं। कई पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई

घटना के बाद मदननगर-धरमपुर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूरजपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन ने बताया कि भूमि अधिग्रहण विवाद के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।

क्या है विवाद की जड़?

यह विवाद केवल भूमि अधिग्रहण का नहीं, बल्कि पुनर्वास की मांग से भी जुड़ा है। ग्रामीण लगातार जमीन के बदले जमीन देने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था, जो अब हिंसक झड़प में बदल गई।

संक्षिप्त खबरें

25 लाख का गांजा समेत आरोपी गिरफ्तार

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। महासमुंद जिला पुलिस के द्वारा दो अलग-अलग स्थान पर करीब 25 लाख से अधिक रुपए का गांजा बरामद किया है इस मामले में एक महिला सहित दो पुरुष को एनडीपीसीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है लिए पहला आरोपी श्रवण यादव अमाव थाना चैनपुर बिहार के पास से करीब 38 किलो गांजा जिसका बाजार मूल्य करीब 19 लख रुपए है को सिंघाड़ा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। वहीं दूसरे मामले में कोमाखान पुलिस के द्वारा मदन तांडी वह शांति टांडी जो उड़ीसा राज्य के निवासी है उनके पास से 12 किलो गांजा बरामद किया गया है जिसका बाजार में मूल्य 6 लाख 37000 अक गया है।

नमूना जांच में आईस कैण्डी मिला अवमानक, संचालक पर 32 हजार जुर्माना

विश्व केसरी

बलौदाबाजार (भुवन लाल)। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में बरसात के मौसम को देखते हुये ढाबा, रेस्टोरेंट एवं होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व जांच में लिये गए आईस कैण्डी के सैंपल जांच में अवमानक पाए जाने पर कोर्ट के निर्देशानुसार संचालक पर 32 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एस.डी. एस गृह उद्योग हटरी बाजार भाटापारा से आईस कैन्डी का नमूना जांच हेतु लिया गया था। जांच में प्रतिबंधित सैकरीन एवं अवांछनीय बाह्य सामग्री पाये जाने के कारण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत् 32000 हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया क्रि शुक्रवार को आंनद फैमिली रेस्टोरेंट, बिलासपुर रोड, लिमतरा से वेज बिरयानी का नमूना, राजेश किराना लिमतरा से मैदा व मूंगफली का नमूना एवं मिलन होटल लिमतरा का निरीक्षण किया गया।, फर्मो को खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने,बासी दूषित खाना विकय नही करने एवं कचड़े अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के निर्देश दिये गये ।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। एम 2 एम रेस्टरोंरेंट बलौदाबाजार से नमूना लिये गये पनीर व बिरयानी राइस अवमानक पाये जाने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

बैंकर्स मीटिंग में डीफ अकाउंट को सक्रिय बनाए रखने के लिए बनी सहमति

विश्व केसरी

बलौदाबाजार (भुवन लाल)। शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की मासिक बैठक जनपद पंचायत कार्यालय भाटापारा के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। बैठक में शासकीय योजना के पुराने खातें जो विभिन्न बैंकों में हैँ जिसमें लेनदेन नहीं हो रहे हैँ ऐसे डीफ खाते का केवायसी लेकर संचालन में लाने अथवा खाता बंद कर राशि अन्य शासकीय योजना के खातों में स्थानांतरित करेने पर बल दिया गया।

बैठक में मुख्यत: शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रधामनंत्री की अतिमहत्वकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर के साथ स्व सहायता समूह लिंकेज एवं ऋण वितरण, एनआरएलएम योजना, कृषको को दिए जाने वाले ऋण किसान क्रेडिट कार्ड,डेयरी व्यवसाय, मछली पालन,पी एम स्वानिधि, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा लोन,अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि पर भी चर्चा हुई.

डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए वित्तीय साक्षरता पर जोर देते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में आरोह एनजीओ संस्था जो सीएफएल के माध्यम से विभिन्न स्थानों में वित्तीय साक्षरता के लिए किए जा रहे कार्यों में बैंक मित्र, एफएलसीआरपी, पीआरपी सहयोग प्रदान करें। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक शिव कुमार कंवर,जनपद सीईओ हिमांशु वर्मा सहित ब्लॉक के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक और ब्लॉक के विभिन्न बैंकों में कार्य कर रहे बैंक मित्र, एफएलसीआरपी, पीआरपी बहुत संख्या में उपस्थित रहे।

भोरिंग स्कूल में शिक्षकों की कमी, सैकड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित : सृष्टि

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोरिंग में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्यापन कराने वाले पांच शिक्षकों का एक साथ प्रशासनिक तबादला कर दिया गया, लेकिन उनके स्थान पर अब तक किसी भी नए शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गई है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में अध्ययनरत सैकड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह स्थिति केवल भोरिंग स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि महासमुंद विकासखंड सहित जिले के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगातार स्थानांतरण के बावजूद रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्रभावी पहल नहीं हो रही है।

जिले की सरकारी शिक्षा व्यवस्था इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। बड़ी संख्या में स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला पंचायत सदस्य सृष्टि अमर चंद्राकर ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासनिक तबादलों के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके चलते नियमित अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्राकर ने कहा कि जिले में कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। इन स्कूलों में 50 से 60 या उससे अधिक विद्यार्थियों को एक ही शिक्षक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी शिक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है।

सरपंच अविश्वास प्रस्ताव गिरा ग्रामीणों में हर्ष का माहौल

विश्व केसरी

कसडोल (प्रवीण कुमार)। विकासखंड कसडोल के समीपस्थ ग्राम पंचायत चरौदा(क)में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरपंच राजकुमार रजक की कुर्सी चली गई है ।सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 24 जुलाई शुक्रवार को हुए मतदान में वे पंचों का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह असफल रहे ।जानकारी के अनुसार,ग्रामीणों और पंचों में सरपंच की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से नाराजगी थी ।इसी के चलते पंचों द्वारा 13 जुलाई को एसडीएम कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया था ।निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुए मतदान में बहुमत सरपंच के खिलाफ गया और वे अपनी कुर्सी नहीं बचा सके ।सरपंच राज कुमार रजक के बर्खास्त होते ही पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई है ।ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए गाँव के विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई है।

जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। जरूरतमंद और प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कूल बैग, नोटबुक, पानी की बोतल, कंपास बॉक्स और पेन सहित अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान की गई। सोहम हॉस्पिटल महासमुंद एवं आस्था वेलफेयर संस्था के संयुक्त सहयोग से शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा को जीवन में सफलता और उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव बताते हुए महासमुंद स्थित श्री राम पाठशाला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सोहम हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉ. सोमी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बच्चों से कहा कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों को अपनी पढ़ाई में बाधा न बनने दें और नियमित रूप से विद्यालय आकर पूरी लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्या रंगारी ने अपने जीवन के अनुभव बच्चों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं मधु तिवारी,लक्ष्मण मानिकपुरी व आस्था वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष विपिन मोहंती ने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन संस्था की सचिव अर्चना शर्मा और लक्ष्मी मानिकपुरी ने संयुक्त रूप से किया। समापन अवसर पर भावना गांधी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, विद्यालय के प्राचार्य, लिनु चंद्राकर, विनोड रंगारी, शिक्षकगण और स्कूल स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे।

शिकायत फाइलों में कैद, कार्रवाई गायब; आरोपित कर्मचारी बेफिक्र

विश्व केसरी

कवर्धा (जगदंबिका साहू)। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) योजना के तहत ग्राम पंचायत बोदा-03 के ग्राम सिली स्थित हुरेसा नाला में 19.25 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिया निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत किए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच शुरू नहीं होने से जिला प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेजों के साथ कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी, परंतु आज तक न तो जांच समिति गठित होने की जानकारी सामने आई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हुई है।

शिकायत में निर्माण कार्य के दौरान स्वीकृत प्राक्कलन की अनदेखी, बिना दिनांक वाले बिलों के आधार पर भुगतान, वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक के बिना बिल प्रस्तुत करने, अपूर्ण इकरारनामा, भारी बारिश के दौरान निर्माण कार्य पूर्ण दर्शाने तथा रेत, गिट्टी और सीमेंट की खरीदी में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं, जिनमें कई गंभीर विसंगतियां सामने आने का दावा किया गया है।

मामले में सबसे गंभीर आरोप निर्माण सामग्री आपूर्ति करने वाली चंद्रवंशी बिल्डिंग मटेरियल एवं बोर खनन, वार्ड क्रमांक 10, बोड़ला (बांधा टोला) से जुड़े हैं। शिकायत के अनुसार जिन बिलों के आधार पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया, उन बिलों में दर्ज पते पर संबंधित

दुकान का अस्तित्व ही नहीं मिला। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है तो मामला केवल एक पुलिया निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जनपद पंचायत बोड़ला में फर्जी बिलों के जरिए शासकीय राशि के बड़े पैमाने पर आहरण का मामला बन सकता है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त फर्म के नाम से केवल ग्राम पंचायत बोदा-03 ही नहीं, बल्कि जनपद पंचायत बोड़ला की कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी निर्माण सामग्री के बिल लगाए गए हैं। यदि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो गड़बड़ी की राशि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद दो महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी लोगों को हैरान कर रही है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य में दो हजार से अधिक सीमेंट की बोरियां, 18 ट्रक और एक ट्रैक्टर गिट्टी तथा 10 ट्रक और 9 ट्रैक्टर रेत उपयोग दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता ने इन सामग्रियों की खरीदी, रॉयल्टी पर्ची, परिवहन अनुमति, मापन पुस्तिका, भुगतान अभिलेख और गुणवत्ता परीक्षण की जांच कराने की मांग की है। लेकिन अब तक किसी प्रकार की जांच आगे नहीं बढ़ने से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शिकायत गलत है तो प्रशासन को जांच कर शिकायत को निराधार घोषित करना चाहिए और यदि शिकायत सही है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दो महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना यह संकेत दे रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रशासन अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहा है।

लगातार हो रही देरी से अब शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लोगों का विश्वास कमजोर पड़ने लगा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब दस्तावेजों के साथ की गई शिकायतों पर भी महीनों तक कार्रवाई नहीं होती, तो आम नागरिक न्याय और पारदर्शिता की उम्मीद किस आधार पर करे।

अब जिलेभर की निगाहें कलेक्टर कार्यालय पर टिकी हैं। लोगों की मांग है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और जनता का प्रशासन पर डगमगाता भरोसा फिर से कायम हो सके।

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक 29 को

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 29 जुलाई को सवेरे 10 बजे कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन मिशन से जुड़े सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

पीएचई विभाग के ईई रूपेश धनंजय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बैठक में मिशन के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें सीआईआरपी के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्यों की प्रगति, पूर्ण हो चुकी 219 योजनाओं के भुगतान की स्थिति एवं लंबित प्रकरण, विद्युत, जल स्रोत एवं हर घर जल योजनाओं के हस्तांतरण से संबंधित विषयों के साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी योजनाओं की अद्यतन प्रगति, आवश्यक अभिलेखों तथा लंबित बिंदुओं की जानकारी के साथ स्वयं अथवा अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहें।

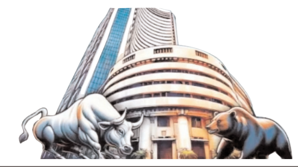

विश्व केसरी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते लगातार पांचवें दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी 0.43 प्रतिशत फिसले

विश्व केसरी

मुंबई । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव के चलते भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस बीच घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्कों सेंसेक्स और निफ्टी 50, दोनों में 0.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार पांचवां सत्र रहा, जब बाजार में गिरावट देखने को मिली।

बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 331.62 अंक यानी 0.43 प्रतिशत गिरकर 76,059.77 पर बंद हुआ, तो वहीं, निफ्टी 50 102 अंक यानी 0.43 प्रतिशत गिरकर 23,767.45 पर बंद हुआ।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,391.39 से 0.89 प्रतिशत यानी 683.2 अंक गिरकर 75,708.19 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 1.20 प्रतिशत यानी 916.96 अंक गिरकर 75,474.43 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 23,869.60 से 0.85 प्रतिशत यानी 203.25 अंक गिरकर 23,666.35 पर खुला और दिन में एक समय यह 1.10 प्रतिशत गिरकर 23,606.30 के इंट्रा-डे लो पर पहुंच गया।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमश: 0.10 प्रतिशत और 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।

वहीं, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा, जिसमें निफ्टी मीडिया 1.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष लाभ कमाने वाला क्षेत्र बनकर उभरा। इसके बाद निफ्टी आईटी में 0.8 प्रतिशत की बढ़त, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.5 प्रतिशत की बढ़त और निफ्टी बैंक में 0.18 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली।दूसरी ओर, निफ्टी ऑटो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा, जिसमें 1.10 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी मेटल में 0.55 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी में 0.57 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी में 0.55 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.46 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा में 0.4 प्रतिशत और निफ्टी इंफ्रा में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में इटरनल, बजाज फाइनेंस, एम एंड एम, श्रीराम फाइनेंस और बजाज-ऑटो शामिल रहे, जबकि सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, सिप्ला, विप्रो, आईटीसी और एचडीएफसी लाइफ शामिल थे।

इस सप्ताह सेंसेक्स में लगभग 2,100 अंकों या 2.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगातार छठे सत्र में वृद्धि जारी रही और ब्रेंट क्रूड का सितंबर अनुबंध 101 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू गया। इस सप्ताह अब तक ब्रेंट क्रूड में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले सप्ताह इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले तीन महीनों से लगातार गिरावट के बाद, ब्रेंट क्रूड जुलाई में अब तक लगभग 40 प्रतिशत ऊपर चढ़ चुका है।

सोने और चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट, कीमतें करीब 0.6 प्रतिशत तक घटीं

विश्व केसरी

मुंबई । सोने और चांदी की शुरुआत शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ हुई। इस दौरान दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 0.6 प्रतिशत तक कम हो गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 1,42,821 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,42,392 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

सुबह 11 बजे यह 870 रुपए या 0.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,41,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

अब तक के कारोबार में सोने ने 1,41,742 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,42,393 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ है।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखी गई।

चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली 2,19,375 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,18,280 रुपए प्रति किलो पर खुला। फिलहाल यह 884 रुपए या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,18,491 रुपए प्रति किलो पर था।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,17,325 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,18,884 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। कॉमैक्स पर सोना 0.48 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,030 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.80 डॉलर प्रति औंस पर था।

कीमती धातुओं में कमजोरी की वजह डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना है, जो कि अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद फिर से 101 के पार पहुंच गया है।

डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं- यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक- के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.24 अरब डॉलर पहुंचा : आरबीआई

विश्व केसरी

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.237 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 964 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी और यह 675.157 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस तरह, लगातार दूसरे सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आरबीआई की वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के मुताबिक, इस वर्ष की शुरुआत में वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आई गिरावट के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत हो रहा है। इससे पहले 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 728.494 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (फॉरेन करेंसी एसेट्स) 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 551.057 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में इन परिसंपत्तियों के मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में होने वाली बढ़त या गिरावट का भी प्रभाव पड़ता है।

वहीं, देश के स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का मूल्य 3.48 अरब डॉलर घटकर 101.749 अरब डॉलर रह गया। इसके अलावा, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 44 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर पर पहुंच गए।

आरबीआई ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की रिजर्व ट्रेंच पोजीशन शामिल होती है। यह भंडार बाहरी आर्थिक झटकों से देश की सुरक्षा करने, रुपए की स्थिरता बनाए रखने और आयात तथा अन्य बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के दौरान रुपए पर दबाव बढ़ने के कारण आरबीआई ने डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया था, जिससे कुछ सप्ताह तक विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ा।

कैबिनेट ने 'भव्या रसायन' स्कीम को दी मंजूरी, देश में तीन केमिकल पार्क होंगे विकसित

विश्व केसरी

मुंबई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शुक्रवार को भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्या - रसायन योजना) को मंजूरी दी। इसके तहत देशभर में तीन केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस स्कीम का ऐलान केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया था।

कैबिनेट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम का संचालन वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 यानी पांच वर्ष के लिए किया जाएगा। इसका कुल बजट 3,030 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं और बुनियादी सेवाएं विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 30 करोड़ रुपए प्रशासनिक खर्च के लिए आवंटित किए गए हैं।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार हर पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपए तक की ग्रांट देगी। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा।

सरकार के मुताबिक, भव्या - रसायन योजना से अर्थव्यवस्था को कई फायदे हैं। इससे केमिकल इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन (जिसमें अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और सहायक इंडस्ट्रीज शामिल हैं) के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे संसाधनों का कुशल इस्तेमाल होगा और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी।

वहीं, केमिकल इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, साझा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और बुनियादी यूटिलिटीज के जरिए लागत के मामले में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता आएगी और भारतीय इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी।

साथ ही, इससे भारतीय केमिकल इंडस्ट्री को ग्लोबल वैल्यू चेन में बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद मिलेगी, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, यह योजना एक पर्यावरण-अनुकूल इकोसिस्टम बनाकर भारतीय केमिकल इंडस्ट्री के टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगी। इस इकोसिस्टम में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटी, और खतरनाक कचरा प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सेंट्रलाइज्ड सुविधाएं शामिल होंगी।

भारत में ऑफिस स्पेस की मांग में दो वर्षों में जीसीसी की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत होने की उम्मीद : रिपोर्ट

विश्व केसरी

नई दिल्ली । भारत में ऑफिस स्पेस की मांग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की हिस्सेदारी दो वर्षों में करीब 50 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में देश की स्थिति और मजबूत होगी। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 और 2027 में भारत में ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस की कुल लीजिंग मांग में जीसीसी की हिस्सेदारी 45-50 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दौरान सालाना लीजिंग 3.5 से 4 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से अब तक जीसीसी ने देश के सात प्रमुख शहरों में करीब 11.8 करोड़ वर्ग फुट ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है, जो इस अवधि के दौरान कुल ऑफिस स्पेस मांग का 37 प्रतिशत है।

सिर्फ 2026 की पहली छमाही में ही जीसीसी ने 1.66 करोड़ वर्ग फुट ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस लीज पर लिया, जो लिए गए कुल ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस का 46 प्रतिशत रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जीसीसी अब केवल पारंपरिक बैक-ऑफिस संचालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रणनीतिक केंद्र बन चुके हैं।

कोलियर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर (ऑफिस सर्विसेज) अर्पित मेहरोत्रा ने कहा, 'भारत ने प्रतिभा, लागत दक्षता, तकनीकी क्षमता, नीतिगत समर्थन और अनुकूल कारोबारी माहौल के दम पर जीसीसी आधारित नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में खुद को मजबूती से स्थापित किया है।'

उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने कैपेबिलिटी सेंटर का विस्तार जारी रखेंगी और एआई आधारित इनोवेशन ऑफिस स्पेस की मांग का प्रमुख चालक बना रहेगा।

क्षेत्रवार देखें तो 2021 से अब तक जीसीसी लीजिंग में टेक्नोलॉजी सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे अधिक 39 प्रतिशत रही।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अब विविधीकरण तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत रही, जबकि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16 प्रतिशत रहा।

2021 से 2025 के बीच बीएफएसआई सेक्टर की लीजिंग लगभग तीन गुना बढ़ी, जबकि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लीजिंग 2.5 गुना से अधिक बढ़ी।

शहरों के लिहाज से बेंगलुरु और हैदराबाद जीसीसी बाजार में सबसे आगे रहे। 2021 से अब तक कुल लीजिंग में इन दोनों शहरों की संयुक्त हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रही।

हालांकि, अब मांग का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है और चेन्नई, पुणे, मुंबई तथा दिल्ली-एनसीआर में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने में बढ़ती रुचि दिखा रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई-नेटिव जीसीसी, नैनो और मिड-साइज जीसीसी एवं 'हब-प्लस-वन' रणनीति के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों तक परिचालन का विस्तार आने वाले वर्षों में जीसीसी क्षेत्र की वृद्धि के अगले चरण को आकार देगा।

एसएमई कंपनियों ने जनवरी-जून में लगभग 80 आईपीओ के जरिए जुटाए 3,752 करोड़ रुपए: रिपोर्ट

विश्व केसरी

नई दिल्ली। देश में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) ने कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून) के दौरान 78 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए कुल 3,752 करोड़ रुपए जुटाए।

शुक्रवार को जारी बी2के एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान जुटाई गई राशि का सबसे बड़ा हिस्सा नए शेयर जारी करने (फ्रेश कैपिटल) से आया, जिससे करीब 3,555 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो कुल इश्यू साइज का लगभग 95 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए 197 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही के 328 करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनियां मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी बेचने के बजाय कारोबार के विस्तार के लिए नई पूंजी जुटाने पर अधिक जोर दे रही हैं।

हालांकि, पहली छमाही 2026 में एसएमई आईपीओ की संख्या पहली छमाही 2025 के 88 और पहली छमाही 2024 के 116 आईपीओ की तुलना में कम रही, लेकिन जुटाई गई कुल राशि पहली छमाही 2025 के 4,004 करोड़ रुपए के मुकाबले केवल मामूली रूप से कम रही। इससे पता चलता है कि कम संख्या में आईपीओ आने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता वाली एसएमई कंपनियों को पूंजी बाजार से पर्याप्त निवेश मिलता रहा।

बी2के एनालिटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रिताबन बसु ने कहा कि पहली छमाही 2026 में एसएमई आईपीओ बाजार की रफ्तार पहले की तुलना में थोड़ी संतुलित रही, लेकिन फंड जुटाने की क्षमता मजबूत बनी रही। उन्होंने कहा कि पहली छमाही 2024 और 2025 की तुलना में आईपीओ की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन कम लिस्टिंग के बावजूद करीब 3,800 करोड़ रुपए जुटाया जाना यह दर्शाता है कि गुणवत्तापूर्ण एसएमई आईपीओ में निवेशकों की रुचि बनी हुई है और विकास पर केंद्रित कंपनियों को इक्विटी पूंजी तक अच्छी पहुंच मिल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में 38 एसएमई कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने करीब 1,891 करोड़ रुपए जुटाए। यह राशि पिछले वर्ष की समान तिमाही में जुटाए गए।

कैबिनेट ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1,264 करोड़ रुपए की मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजना को दी मंजूरी

विश्व केसरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंटकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर कुल 1,264 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह मल्टीट्रैकिंग परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में फैली हुई है, जिसके तहत भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। परियोजना को वर्ष 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस परियोजना से लगभग 99 गांवों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जहां करीब 7 लाख लोग रहते हैं। साथ ही, बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर सहित देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क भी मजबूत होगा।

बयान के अनुसार, यह रेलमार्ग लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा एवं इस्पात, कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी प्रमुख वस्तुओं के परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परियोजना पूरी होने के बाद माल ढुलाई क्षमता में प्रतिवर्ष 16.22 मिलियन टन (एमटीपीए) की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

सरकार ने कहा कि रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन माध्यम है।

इस नेटवर्क विस्तार से देश के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इससे लगभग 1.32 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी और 6.67 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 27 लाख पेड़ लगाने के बराबर मानी गई है।यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है। इसके माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही अधिक सुगम होगी।

सरकार के अनुसार, अतिरिक्त रेल लाइन बनने से रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिचालन दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा। यह परियोजना रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम करने और संचालन को अधिक सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बयान में कहा गया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नया भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप है, जिसके माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सावन में ऑफिस भी, स्टाइल भी! कामकाजी महिलाओं के लिए 10 मिनट में बनने वाले आसान मेहंदी की डिजाइन्स

सावन का महीना आते ही हर तरफ हरियाली, झूले, पूजा-पाठ और त्योहारों की रौनक दिखाई देने लगती है. इस मौसम में मेहंदी लगाना भी एक खूबसूरत परंपरा का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जो महिलाएं रोज ऑफिस जाती हैं, उनके लिए घंटों बैठकर भारी-भरकम मेहंदी डिजाइन बनवाना हमेशा आसान नहीं होता. सुबह की जल्दी, ऑफिस का समय और घर की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर मेहंदी लगाने का समय ही नहीं मिल पाता. ऐसे में सिंपल, स्टाइलिश और जल्दी बनने वाले मेहंदी डिजाइन सबसे अच्छा ऑप्शन साबित होते हैं।

सिंपल लेकिन बेहद आकर्षक अगर आपके पास बहुत कम समय है तो हथेली के बीच गोल मंडला डिजाइन बनाना सबसे आसान ऑप्शन है. इसके चारों तरफ छोटी-छोटी पत्तियां, डॉट्स और हल्के पैटर्न जोड़कर डिजाइन को और सुंदर बनाया जा सकता है. यह डिजाइन पारंपरिक होने के साथ-साथ काफी मॉडर्न भी लगता है।

फिंगर मेहंदी डिजाइन आजकल सिर्फ उंगलियों पर मेहंदी लगाने का ट्रेंड काफी लोकप्रिय हो गया है. इसमें पूरी हथेली भरने की जरूरत नहीं होती. उंगलियों पर बेल, डॉट्स और छोटे फूलों का पैटर्न बनाकर कुछ ही मिनटों में खूबसूरत लुक पाया जा सकता है. ऑफिस पहनावे के साथ यह डिजाइन काफी अच्छा लगता है।

फ्लोरल पैटर्न हमेशा रहता है ट्रेंड में छोटे-छोटे फूलों और पत्तियों से तैयार फ्लोरल डिजाइन कभी पुराने नहीं पड़ते. इन्हें हथेली के एक हिस्से में या हाथ के किनारे बनाया जा सकता है. यह डिजाइन कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर कामकाजी महिलाओं तक सभी पर खूब जंचता है।

बेल स्टाइल मेहंदी डिजाइन अगर आपको क्लासी लुक पसंद है तो बेल डिजाइन बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. कलाई से शुरू होकर उंगलियों तक जाने वाली पतली बेल हाथों को लंबा और आकर्षक दिखाती है. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती।

फ्रंट और बैक हैंड का कॉम्बिनेशन अगर समय थोड़ा ज्यादा है तो सामने की हथेली पर हल्का डिजाइन और हाथ के पीछे छोटी बेल या फूलों का पैटर्न बनाया जा सकता है. इससे हाथ भरे हुए भी लगते हैं और डिजाइन ज्यादा भारी भी नहीं दिखता.

ऑफिस लुक के साथ कैसे करें मेहंदी को स्टाइल? सिंपल मेहंदी डिजाइन कुर्ती, कॉटन साड़ी, फॉर्मल सूट और इंडो-वेस्टर्न ड्रेस सभी के साथ अच्छे लगते हैं. हल्की चूड़ियां, छोटी बिंदी और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ यह लुक और भी आकर्षक बन जाता है. यही वजह है कि कई कामकाजी महिलाएं भारी डिजाइन की जगह मिनिमल पैटर्न चुन रही हैं।

मेहंदी का रंग गहरा लाने के आसान उपाय मेहंदी लगाने के बाद उसे कम से कम 5 से 6 घंटे तक सूखने दें. सूखने पर नींबू और चीनी का हल्का मिश्रण लगाना फायदेमंद माना जाता है. मेहंदी हटाने के बाद तुरंत पानी से हाथ धोने की बजाय सरसों या नारियल का तेल लगाने से रंग लंबे समय तक टिक सकता है।

पेट की चर्बी घटाने के लिए क्या करें? केवल तेज चलना काफी या बेहतर नतीजों के लिए दौड़ना शुरू करना चाहिए

यदि आपका टारगेट कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करना है, तो रनिंग बेहतर विकल्प हो सकती है. पर अगर आप ऐसी एक्सरसाइज चाहते हैं जिसे रोजाना आसानी से किया जा सके और जिसका शरीर पर कम प्रभाव पड़े, तो वॉकिंग भी उतनी ही अच्छी है. लेकिन हमेशा अपने लिए सही विकल्प चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिन्हें आप यहां लेख में जान सकते हैं।

इसमें कोई दोराय नहीं कि वजन घटाने और फिट रहने के लिए वॉकिंग और रनिंग दोनों ही फायदेमंद मानी जाती हैं. हालांकि, पेट की चर्बी कम करने के मामले में किसी एक को सबसे बेहतर कहना आसान नहीं है. यह समझना जरूरी है कि शरीर के किसी एक हिस्से की चर्बी को अलग से कम नहीं किया जा सकता. पेट की चर्बी घटाने के लिए पूरे शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करनी होती है. इसके लिए कैलोरी डेफिसिट यानी जितनी कैलोरी आप लेते हैं उससे ज्यादा कैलोरी खर्च करना जरूरी है।

ये समझना जरूरी है कि नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर शरीर की कुल चर्बी को कम किया जा सकता है, जिससे कमर और पेट के आसपास जमा फैट भी धीरे-धीरे घटने लगता है. ऐसे में वॉकिंग और रनिंग दोनों की अपनी-अपनी खासियतें हैं, जिन्हें समझकर आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकते हैं। दौड़ना एक हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इसलिए यह चलने की तुलना में कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करती है. अधिक कैलोरी खर्च होने से फैट लॉस के लिए जरूरी कैलोरी डेफिसिट बनाना आसान हो जाता है. यदि आपके पास समय कम है और आप शारीरिक रूप से दौड़ने में सक्षम हैं, तो रनिंग एक प्रभावी विकल्प हो सकती है।

वहीं, चलना एक ऐसी गतिविधि है जिसे लंबे समय तक नियमित रूप से करना आसान होता है. इसमें किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती और यह लगभग हर उम्र और फिटनेस स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त है. रोजाना 30 से 60 मिनट की वॉक समय के साथ वजन और शरीर की चर्बी कम करने में मदद कर सकती है।

रंग-बिरंगी शिमला मिर्च में क्या अंतर होता है? जानिये इसके स्वाद और सेहत पर असर

शिमला मिर्च के हरे, पीले और लाल रंग पकने की अलग-अलग अवस्थाएं हैं. हरी सबसे कम पकी, तीखी और सस्ती होती है, जबकि लाल सबसे पकी, मीठी और महंगी होती है। शिमला मिर्च एक पौष्टिक और रंग-बिरंगी सब्जी है, जिसका उपयोग भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के व्यंजनों में व्यापक रूप से किया जाता है. बाजार में मुख्य रूप से हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च उपलब्ध होती हैं. बहुत से लोग इन्हें अलग-अलग किस्मों की सब्जी समझते हैं, जबकि वास्तव में ये एक ही पौधे के फल हैं, जो पकने की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं. रंग बदलने के साथ-साथ इनके स्वाद, पोषण मूल्य, कीमत और उपयोग में भी अंतर आ जाता है।

हरी शिमला मिर्च

हरी शिमला मिर्च सबसे कम पकी हुई अवस्था में तोड़ी जाती है. इसका स्वाद अन्य रंगों की तुलना में थोड़ा तीखा और हल्का कड़वा होता है. यही कारण है कि भारतीय सब्जियों, नूडल्स, पनीर और चाइनीज व्यंजनों में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है. हरी शिमला मिर्च में कैलोरी कम होती है और विटामिन ष्ट अच्छी मात्रा में पाया जाता है. कम समय में तैयार हो जाने के कारण इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम होती है।

पीली शिमला मिर्च

पीली शिमला मिर्च हरी अवस्था से आगे बढ़कर अधिक पकने पर तैयार होती है. इसका स्वाद हरी शिमला मिर्च की तुलना में अधिक मीठा और कम कड़वा होता है. पीला रंग इसे आकर्षक बनाता है, इसलिए इसका उपयोग सलाद, सैंडविच, पास्ता तथा भोजन की सजावट में अधिक किया जाता है।

रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट और मसालेदार एग करी बनाना चाहते हैं, तो नोट करें ये रेसिपी

एग करी भारतीय रसोई की एक लोकप्रिय, स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर डिश है. इसे उबले अंडे और मसालेदार ग्रेवी से बनाया जाता है. इसे रोटी, नान या चावल के साथ परोस सकते हैं।

एग करी भारतीय रसोई की एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट डिश है, जिसे उबले हुए अंडों और मसालेदार ग्रेवी के साथ तैयार किया जाता है. यह रेसिपी न केवल बनाने में आसान है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. एग करी को रोटी, पराठा, नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है. यदि आप घर पर ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहते हैं, तो यह रेसिपी जरूर आजमाएं।

आवश्यक सामग्री

अंडों के लिए
6 उबले हुए अंडे
½ छोटा चम्मच हल्दी
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 बड़ा चम्मच तेल

ग्रेवी के लिए
2 बड़े प्याज (बारीक कटे हुए)
3 टमाटर (प्यूरी बनाए हुए)
1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
2 हरी मिर्च (कटी हुई)
1 छोटा चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
½ छोटा चम्मच गरम मसाला
½ छोटा चम्मच कसूरी मेथी
नमक स्वादानुसार
2 बड़े चम्मच तेल
हरा धनिया सजावट के लिए

अंडे तैयार करने की विधि

सबसे पहले उबले हुए अंडों का छिलका निकाल लें. अंडों पर हल्के कट लगा दें ताकि मसाले अच्छी तरह अंदर तक पहुंच सकें. अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें हल्दी तथा लाल मिर्च पाउडर डालें. तुरंत अंडों को डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे अंडों का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है।

ग्रेवी बनाने की विधि

एक कड़ाही में तेल गर्म करें और जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो उसमें बारीक कटे प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक पकाएं।

अब टमाटर की प्यूरी डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालें. मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे. यह कदम एग करी को गहरा और लाजवाब स्वाद देता है।

जब मसाला अच्छी तरह पक जाए, तब आवश्यकतानुसार पानी डालकर ग्रेवी तैयार करें. ग्रेवी में उबाल आने पर भुने हुए अंडे डाल दें. कड़ाही को ढककर 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि अंडों में मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए.

अंत में गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर मिलाएं. गैस बंद कर दें और ऊपर से ताजा हरा धनिया छिड़कें।

परोसने का तरीका

गरमा-गरम एग करी को सादे चावल, जीरा राइस, तंदूरी रोटी, नान या पराठे के साथ परोसें. साथ में प्याज का सलाद और नींबू परोसने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

जिंदगी में बहुत देर से समझ आती हैं रिश्तों की ये 7 बातें, पहले हो जाए पता कभी न टूटे प्यार और भरोसा

प्यार के रिश्ते में सिर्फ 'आई लव यू' कहना काफी नहीं होता. साइकोलॉजी और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जानिए वे 7 कड़वे मगर सच्चे सबक जो अक्सर लोग बहुत देर से समझ पाते हैं. जानें कि कैसे ये छोटी-छोटी बातें आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकती हैं और उसमें सुकून ला सकती हैं।

प्यार के रिश्ते में सिर्फ 'आई लव यू' कहना काफी नहीं होता. साइकोलॉजी और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जानिए वे 7 कड़वे मगर सच्चे सबक जो अक्सर लोग बहुत देर से समझ पाते हैं. जानें कि कैसे ये छोटी-छोटी बातें आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकती हैं और उसमें सुकून ला सकती हैं।

1.सिर्फ प्यार काफी नहीं होता

रिश्ते की शुरुआत प्यार से हो सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाने के लिए भरोसा, सम्मान और मेहनत जरूरी होती है. अगर इन तीन चीजों की कमी हो, तो गहरा प्यार भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है।

2.मन की बात कहें

कई लोग उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर बिना बताए उनकी हर भावना समझ जाएगा. लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती. अगर कोई बात परेशान कर रही है, तो उसे प्यार और शांति से कहें. खुलकर बातचीत करने वाले कपल्स के रिश्ते ज्यादा मजबूत माने जाते हैं।

नैनीताल, भीमताल, सातताल से अलग... बेहद खूबसूरत हैं आसपास की ये हिडन लोकेशन, जहां नहीं पहुंच पाते ज्यादातर टूरिस्ट

उत्तराखंड का नैनीताल सिर्फ नैनी झील, मॉल रोड और स्नो व्यू तक ही सीमित नहीं है. शहर के आसपास कई ऐसे खूबसूरत और शांत पर्यटन स्थल भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यही वजह है कि यहां पर्यटकों की भीड़ भी नहीं होती और प्रकृति का असली आनंद लेने का मौका मिलता है. अगर आप इस बार नैनीताल की यात्रा पर आ रहे हैं, तो इन जगहों पर जरूर जाएं.

नैनीताल से कुछ दूरी पर स्थित विनायक प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन जगह है. यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. घने देवदार और बांज के जंगल इस स्थान को और आकर्षक बनाते हैं. यहां पर्यटकों की भीड़ कम रहती है, इसलिए सुकून से समय बिताया जा सकता है. सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता है. फोटोग्राफी के लिए भी यह शानदार लोकेशन है, अगर आप शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं, तो नैनीताल के पास स्थित विनायक जरूर जाएं.

मंगोली नैनीताल के पास स्थित एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहां से झील, पहाड़ और घाटियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है. यह जगह अब धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है, लेकिन अभी भी यहां ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती. सुबह और शाम का नजारा बेहद आकर्षक होता है. शांत वातावरण के कारण यह परिवार और कपल्स दोनों के लिए पसंदीदा स्थान बन सकता है. यहां से फोटो और वीडियो बेहद शानदार आते हैं. प्रकृति के बीच कुछ पल बिताने के लिए यह बेहतरीन विकल्प है.

आलूखेत नैनीताल का एक शांत और हरियाली से भरपूर इलाका है. यहां दूर-दूर तक फैले जंगल और खुला प्राकृतिक वातावरण मन को सुकून देता है. भीड़भाड़ से दूर होने के कारण यह जगह पिकनिक, फोटोग्राफी और प्रकृति के बीच समय बिताने वालों के लिए उपयुक्त है. यहां का मौसम सालभर सुहावना बना रहता है. पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा इस स्थान को और खास बना देती है. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर आराम चाहते हैं, तो आलूखेत आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. नैनीताल के पास होने के बावजूद भी यह जगह हिडन है, अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो इस जगह पर जरूर आएं.

नैनीताल के पास स्थित शीतला बेहद खूबसूरत और प्रकृति के रंगों से सराबोर है, यह जगह पहाड़ों की गोद में बसी हुई है।

यहां से दिखने वाले हिमालय के खूबसूरत नजारे आपका दिल छू जाएंगे. यहां स्थित महादेव के मंदिर में स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा है. पहाड़ों और जंगलों से घिरा यह स्थान बेहद शांत माहौल प्रदान करता है. मानसून और सर्दियों में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है. फोटोग्राफी और आध्यात्मिक अनुभव के लिए यह शानदार जगह मानी जाती है।

'टीवी सबसे बड़ा स्कूल है, लोग इसे कम क्यों समझते हैं?'

निहारिका चौकसे ने इंडस्ट्री की सोच पर उठाए सवाल

'तुम से तुम तक' में आ रहीं हैं नज़र

मुंबई। टेलीविजन अभिनेत्री निहारिका चौकसे इन दिनों अपने शो 'तुम से तुम तक' को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में टेलीविजन इंडस्ट्री को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाया है जो आज के समय में टीवी को फिल्मों और ओटीटी से कमतर मानते हैं। उनका कहना है कि टीवी कलाकारों के लिए सबसे बड़ा स्कूल है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है।

मीडिया से बात करते हुए निहारिका चौकसे ने कहा, ''मुझे टीवी पर काम करना हमेशा पसंद आता है। अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे रोज 14 घंटे काम करना होगा, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग टेलीविजन को कम क्यों आंकने लगते हैं। मेरे लिए टीवी सबसे बड़ा स्कूल है। यहां कैमरे के सामने अभिनय करना, लंबी-लंबी लाइन्स याद करना और हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करना सीखने को मिलता है।

उन्होंने आगे कहा, ''टेलीविजन में काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां कलाकारों को बहुत कम समय में अपना बेस्ट देना पड़ता है। टीवी में अगले दिन का एपिसोड प्रसारित होना होता है, इसलिए नई स्क्रिप्ट मिलते ही कलाकारों को तुरंत तैयारी करनी पड़ती है और शूटिंग भी करनी होती है। वेब सीरीज में कलाकारों को वर्कशॉप और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन टीवी में काम की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होती है। यही वजह है कि टीवी कलाकारों को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है।

निहारिका चौकसे ने कहा, 'मनोरंजन जगत अब पहले से बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलाव जीवन का सबसे बड़ा सच है और इंडस्ट्री भी समय के साथ बदल रही है। पहले टेलीविजन में महिलाओं पर आधारित कहानियां ज्यादा देखने को मिलती थीं, लेकिन अब फिल्मों में भी महिला कलाकारों को मजबूत और अहम किरदार मिलने लगे हैं। महिला प्रधान फिल्मों का अच्छा प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि दर्शकों की सोच बदल रही है और इंडस्ट्री महिलाओं को पहले से ज्यादा अवसर दे रही है।'

रियलिटी शोज में आने को लेकर भी निहारिका ने कहा, ''अभी मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं। रियलिटी शोज बाद में भी किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना फैन बेस मजबूत करना चाहती हूं, ताकि जब भी किसी रियलिटी शो में हिस्सा लूं, तो जीतने के इरादे से जाऊं। उन्होंने कहा, 'मुझे डांस करना बेहद पसंद है, इसलिए 'झलक दिखला जा' मेरे पसंदीदा रियलिटी शोज की लिस्ट में शामिल है।

रियलिटी शो पर रखी अपनी बात

निहारिका ने कहा, "अभी मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं। रियलिटी शोज बाद में भी किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना फैन बेस मजबूत करना चाहती हूं, ताकि जब भी किसी रियलिटी शो में हिस्सा लूं, तो जीतने के इरादे से जाऊं।"

झलक दिखला जर पसंदीदा शो

उन्होंने कहा, "मुझे डांस करना बेहद पसंद है, इसलिए 'झलक दिखला जा' मेरे पसंदीदा रियलिटी शोज की लिस्ट में शामिल है। वहीं, 'खतरों के खिलाड़ी' में हिस्सा लेने की इच्छा भी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने डर पर काबू पाना चाहती हूं।"

आने वाले प्रोजेक्ट ★ निहारिका चौकसे जल्द ही 'तुम से तुम तक' में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती नज़र आएंगी।

अभिनेत्री आंचल सिंह ने निवेश बैंकर मोहित चावला से की शादी, बताया विवाह का सही मतलब

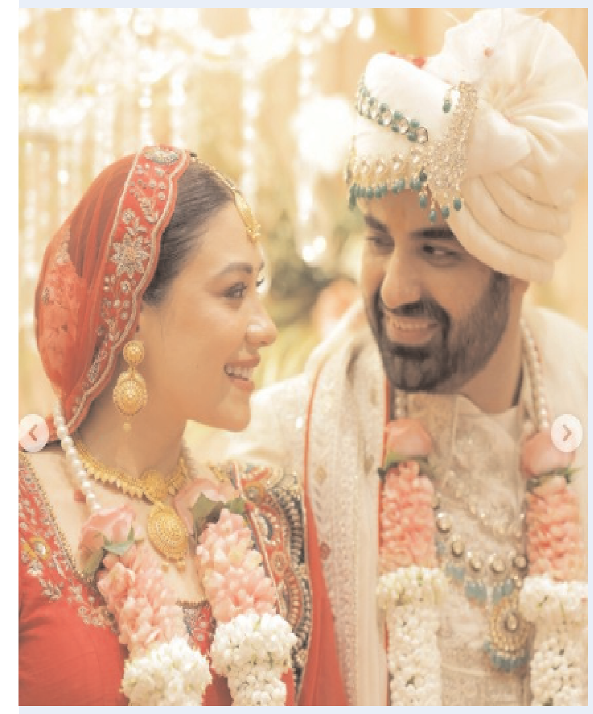

विश्व केसरी

मुंबई। अभिनेत्री आंचल सिंह ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और निवेश बैंकर मोहित चावला से शादी कर ली। शुक्रवार को अभिनेत्री ने इस खूबसूरत पल की तस्वीरें शेयर कीं।

आंचल सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। अपनी इस पोस्ट के जरिए अभिनेत्री ने अपने मन के विचार शेयर करते हुए बताया कि शादी का मतलब अपना घर छोड़ना नहीं, बल्कि जीवन में नए रिश्तों और प्यार को जगह देना होता है। इसकी असली खूबसूरती इस बात में है कि आपके जीवन में प्यार करने वाले और लोग जुड़ जाते हैं।

उन्होंने लिखा, ''तुम' और 'मैं' से 'हम' तक... हमेशा के लिए। कुछ पल ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। रस्मों के बीच एक-दूसरे की ओर देखा गया एक प्यार भरा नजरिया। एक मुस्कान, जो कहती है सच में अब हम साथ हैं। जुड़े हुए हाथों से की गई एक शांत प्रार्थना और मांग में सजे सिंदूर के साथ निभाने का एक जीवनभर का वादा। जब मैं इन खूबसूरत पलों को याद करती हूं, तो एक बात बार-बार मन में आती है। मैं हमेशा से मानती हूं कि शादी के बाद बेटी अपने मायके से जुड़ी नहीं रहती, ऐसा नहीं होता। वह अपने पहले घर को दिल में बसाए हुए एक नए घर और नए परिवार का हिस्सा बनती है।

उन्होंने कहा कि शादी के बाद इंसान की दुनिया धीरे-धीरे और बड़ी हो जाती है। उसके जीवन में प्यार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। आशीर्वाद बढ़ते हैं और उसे एक नया परिवार भी अपना कहने का सौभाग्य मिलता है। उन्होंने लिखा, 'शायद यही शादी की सबसे खूबसूरत बात है। यह किसी अपने को छोड़ने की नहीं या किसी और का हो जाने की बात नहीं है, बल्कि उस पल की शुरुआत है, जब आपकी दुनिया और बड़ी हो जाती है, जहां प्यार करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, दुआएं और आशीर्वाद बढ़ जाते हैं और आपको एक नया परिवार भी अपना कहने का सौभाग्य मिलता है।'

उन्होंने लिखा, 'हम दोनों, परिवारों और उन सभी परंपराओं के लिए है, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। उन सभी आशीर्वादों के लिए है, जो हमारे साथ हैं और उन सभी खूबसूरत यादों के लिए है, जो अभी बननी बाकी हैं। हमेशा के लिए।

राम संपत : जिंगल लिखने से करियर की शुरुआत, ऐसे बने बॉलीवुड के हिट म्यूजिक डायरेक्टर

मुंबई। संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राम संपत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई यादगार धुनें दी हैं, लेकिन उनकी सफलता की कहानी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है। एक समय था जब राम संपत विज्ञापनों के लिए छोटे-छोटे जिंगल तैयार किया करते थे और आज वही नाम हिंदी सिनेमा के बेहतरीन संगीतकारों में गिना जाता है।

राम संपत का जन्म 25 जुलाई, 1977 में मुंबई में हुआ था। उनके माता-पिता दोनों ही संगीत प्रेमी थे। बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिलने के कारण राम का झुकाव भी सुर और धुनों की दुनिया की तरफ बढ़ता गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ओएलपीएस हाई स्कूल से की और इसके बाद पोदार कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की।

संगीत के प्रति जुनून ने उन्हें विज्ञापन की दुनिया तक पहुंचाया। फिल्मों में आने से पहले राम संपत ने कई बड़े ब्रांड्स के लिए जिंगल बनाए। टाटा डोकोमो, एयरटेल, थम्स अप, पेप्सी, टाइम्स ऑफ इंडिया, सर्फ एक्सेल और कई अन्य कंपनियों के विज्ञापनों में उनकी बनाई धुनें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुईं।

इसके बाद राम संपत ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। साल 2002 में आई फिल्म 'लेट्स टॉक' से उन्होंने बतौर संगीत निर्देशक अपना सफर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 'खाकी' और 'फैमिली' जैसी फिल्मों में संगीत दिया।

हालांकि उन्हें असली पहचान साल 2011 में आई फिल्म 'डेली बेली' से मिली।

'कुछ लोग मेरे काम के अवसरों को रोक रहे हैं', तनुश्री दत्ता ने ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स से की सावधानी बरतने की अपील

विश्व केसरी

मुंबई। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने काम और प्रोफेशनल अवसर को लेकर चिंता जाहिर की।

उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो उनके साथ काम करने के इच्छुक लोगों और ब्रांड्स तक पहुंच बनाकर उनके प्रोजेक्ट्स में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तनुश्री ने अपनी पोस्ट के जरिए ब्रांड्स, इवेंट आयोजकों और फिल्म से जुड़े लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है।

तनुश्री दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन विरोधी कैंप के लोग उन्हें मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहे। वे झूठ बोलते हैं, चीजों को गलत तरीके से पेश करते हैं और शुरुआत में ही बातचीत को गलत दिशा में ले जाते हैं।

वे असली ब्रांड्स, इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सके।''

तनुश्री ने अपनी पोस्ट में ब्रांड्स और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को सावधान किया और कहा कि उनके नाम पर किसी भी तरह के भुगतान से पहले पूरी तरह जांच कर ले। उनके काम से जुड़े सभी लेन-देन एक तय प्रक्रिया के तहत होते हैं, और वह केवल अपने ऑफिशियल बैंकिंग अकाउंट के जरिए ही भुगतान लेती हैं।

अभिनेत्री ने लिखा, ''किसी भी ब्रांड, इवेंट आयोजक या फिल्म टीम से मेरी अपील है कि जब तक भुगतान मेरे एकमात्र ऑफिशियल बैंकिंग अकाउंट में न हो, तब तक कोई पैसा ट्रांसफर न करें। मैं किसी भी तरह का कैश ट्रांजेक्शन नहीं करती। मेरा पूरा काम कानूनी तरीके से होता है और सभी भुगतान सरकारी नियमों के अनुसार किए जाते हैं।

आरती सिंह ने कश्मीरा शाह और कृष्णा की शादी की सालगिरह पर लिखा इमोशनल नोट

मुंबई। अभिनेता और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपनी पत्नी और अभिनेत्री कश्मीरा शाह के साथ शुक्रवार को शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर कृष्णा की छोटी बहन और अभिनेत्री आरती सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी।

अभिनेत्री आरती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर भाई और भाभी (कश्मीरा शाह और कृष्णा) की पुरानी कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इसमें दोनों के साथ में बिताए यादगार पल शामिल हैं।

अभिनेत्री ने कश्मीरा शाह को कृष्णा की रक्षक बताते हुए लिखा, 'आप दोनों का रिश्ता समय के साथ-साथ खास और मजबूत रिश्ता बन गया है। मुश्किल हो या अच्छा दिन, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, जैसे भाभी कश्मीरा शाह कहती हैं कि वह कृष्णा को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। यह मैंने इन सभी सालों में अपनी आंखों से देखा है।

अभिनेत्री आरती सिंह ने बताया कि कश्मीरा शाह अभिषेक के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने लिखा, 'अगर कोई कृष्णा की तरफ उंगली भी उठाए, तो वह उसके लिए भी लड़ने को तैयार हो जाएंगी। वह सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी रक्षक और उनकी पूरी दुनिया हैं और कृष्णा भी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। यही एक सच्चे रिश्ते की पहचान है। सबसे अच्छे कपल और दोस्त। भाई और भाभी को शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। आप दोनों को बहुत सारा प्यार।'

अभिनेता और कमेडियन कृष्णा अभिषेक ने भी इंस्टाग्राम के जरिए पत्नी कश्मीरा शाह को सालगिरह की बधाई दी।

'ईमानदारी को लोग घमंड समझ लेते हैं', घमंडी कहे जाने पर करण पटेल ने दिया जवाब

विश्व केसरी

मुंबई। अभिनेता करण पटेल किसी भी मुद्दे पर अपनी सोच खुलकर रखने से पीछे नहीं हटते, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार 'रूड' और 'एरोगेंट' जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता है। अब इस पर करण पटेल ने कहा कि कई बार लोग सच बोलने और अपनी बात रखने को गलत समझ लेते हैं।

मीडिया से खास बातचीत में करण पटेल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और वह दूसरों की सोच को लेकर परेशान नहीं होते। उन्होंने कहा, ''आज के समय में कई बार लोग ईमानदारी और सीधेपन को घमंड या बदतमीजी समझ लेते हैं। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मेरी बात सही हो और कुछ लोगों के लिए गलत, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सोच रखने का पूरा हक है।

करण पटेल ने आगे कहा, ''किसी और की राय को लेकर दूसरों को फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। हर इंसान का नजरिया अलग होता है और राय भी। आप अपनी राय और पसंद अपने तक रखें। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, तो उसे पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि करण पटेल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते है। वह देश, समाज और मनोरंजन जगत से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते है। अपनी सीधी बात कहने की वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है।

करण पटेल ने टेलीविजन इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता एकता कपूर के चर्चित शो 'ये है मोहब्बतें' से मिली, जिसमें उन्होंने रमन भल्ला का किरदार निभाया था। इस किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और वह टीवी के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में शामिल हो गए।

इसके अलावा करण पटेल ने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया है। इनमें 'कस्तूरी', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'कसम से' और रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 10' जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। वह हाल ही में रिलीज हुए शो 'रक्तांचल सीजन 3' में नजर आए थे।

राष्ट्रपति मुर्मु ने भारत-रोमानिया व्यापार मंच को किया संबोधित

इंडिया-ईयू एफटीए के क्रियान्वयन पर दिया जोर

विश्व केसरी

बुखारेस्ट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 24 जुलाई को बुखारेस्ट में भारत-रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन, रोमानिया सरकार के सदस्यगण, भारत और रोमानिया के बिजनेस लीडर्स और दोनों देशों के उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप के प्रमुख संपर्क बिंदु पर स्थित रोमानिया अपनी रणनीतिक स्थिति, अत्यन्त कुशल मानव संसाधन, उन्नत औद्योगिक क्षमता और यूरोपीय संघ के साथ सुदृढ़ एकीकरण के कारण भारत का एक स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। रोमानिया न केवल निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है बल्कि यह वृहत्तर यूरोपीय बाजार का प्रवेश द्वार भी है।

उन्होंने कहा कि इस मंच पर बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी, रोमानिया में विद्यमान अवसरों के प्रति भारतीय उद्योगों के बढ़ते विश्वास और रोमानियाई व्यवसायों के साथ स्थायी साझेदारी बनाने की उनकी इच्छा को व्यक्त करती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार और आर्थिक सहयोग भारत और यूरोपीय संघ की समकालीन साझेदारी का प्रमुख आधार हैं। लगभग दो अरब लोगों के संयुक्त बाजार और लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारियों में से एक है। इसका उद्देश्य व्यापारिक एकीकरण को और गहरा करना, निवेश के प्रवाह में तेजी लाना तथा सशक्त एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एफटीए का शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा। इससे कारोबार के लिए विश्वसनीय परिवेश तैयार होगा, मूल्य श्रृंखलाओं का एकीकरण मजबूत होगा तथा दोनों पक्षों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप और नवाचारकर्ताओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 'विकसित भारत 2047' का हमारा संकल्प, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है।

बलूचिस्तान के खुजदार में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में एक की मौत

विश्व केसरी

क्वेटा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक और व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि बलूचिस्तान के खुजदार जिले में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और महिलाओं व बच्चों समेत कई अन्य घायल हो गए। यह घटना खुजदार में वाध के ड्राखाला-गैसलाती इलाके में हुई। गोलीबारी के बाद वहां के लोगों ने हाईवे पर धरना दिया और मृतक अब्दुल कादिर का शव प्रदर्शन वाली जगह पर रख दिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी गुरुवार सुबह शुरू हुई और वाध के एक आम इलाके में हुई। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की मांग की और स्पष्ट जांच होने तक धरना जारी रखने की कसम खाई। घटना की निंदा करते हुए बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के चेयरमैन नसीम बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'आम लोगों के इलाकों पर गोलाबारी, लोगों को जबरदस्ती गायब करना, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के हत्याएं, हिरासत में मौतें और सामूहिक सजा, चल रहे संघर्ष की लगातार बनी हुई बातें बन गई हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की तुरंत जरूरत पर जोर पड़ता है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र, स्वतंत्र मीडिया और मानवाधिकार संगठनों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बलूचिस्तान में बिना किसी रोक-टोक के पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वहां की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके, मानवाधिकार हालात की निगरानी की जा सके और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। गुरुवार को मानवाधिकार संगठन बलोच वॉयस फॉर जस्टिस (बीवीजे) ने बलूचिस्तान के कई इलाकों, खांड कोटचा, जेहरी, नौशकी और जिवानी में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लंबे समय से लगाए गए कर्फ्यू, इंटरनेट बंदी और आवाजाही पर प्रतिबंध को लेकर गंभीर चिंता जताई।

संक्षिप्त खबर

बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी, दो बच्चों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 805 पहुंचा

विश्व केसरी

ढाका। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी है। गुरुवार को इस बीमारी जैसे लक्षणों वाले दो और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 805 हो गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के मुताबिक, गुरुवार सुबह तक के पिछले 24 घंटों में ये दो मौतें दर्ज की गईं। बांग्लादेशी समाचार एजेंसी 'यूएनबी' के अनुसार, इन दोनों मौतों को फिलहाल संदिग्ध खसरे से हुई मौत माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, खसरे से हुई पुष्टि की गई मौतों की संख्या अभी भी 95 है, लेकिन संदिग्ध मौतों का आंकड़ा बढ़कर 710 हो गया है। डीजीएचएस ने पिछले 24 घंटों में खसरे के 848 नए संदिग्ध मामले दर्ज किए। इसके साथ ही 15 मार्च से अब तक संदिग्ध मामलों की कुल संख्या 1,21,200 हो गई है। इसी दौरान खसरे के 166 नए पुष्टि किए गए मामले भी सामने आए, जिससे कुल पुष्टि किए गए मामलों की संख्या बढ़कर 15,007 हो गई। बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खसरे से हर दिन औसतन लगभग चार बच्चों की मौत हो रही है और रोज 800 से ज?यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। वहीं, सरकार की कोशिशें और लोगों का ध्यान दोनों पहले की तुलना में कम होते दिख रहे हैं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का इस्तीफा, तय समय से दो साल पहले छोड़ दिया पद

विश्व केसरी

ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, संसद के स्पीकर ने उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति का पद संभाला था। वह जुलाई 2024 के प्रदर्शनों के बाद देश के इकलौते ऐसे बड़े संवैधानिक पदाधिकारी थे, जो अपने पद पर बने हुए थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक चलना था, लेकिन उन्होंने तय समय से करीब दो साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' से बात करते हुए शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। मैं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा हूं। फिलहाल, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 'द डेली स्टार' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शहाबुद्दीन के इस्तीफे की खबर ऐसे समय आई है, जब यह रिपोर्ट सामने आई कि इस साल मई में इलाज के लिए लंदन जाने के दौरान उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में खुफिया एजेंसियों को इस बातचीत की जानकारी मिली, जिसके बाद राष्ट्रपति से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हालांकि, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि सिर्फ यही फोन कॉल इस्तीफे की वजह नहीं थी।

यूएन में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, पीओके में दमन पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी को लेकर उठाए

विश्व केसरी

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति निराशा जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान, खासकर उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे दमन को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि अन्य देशों में ऐसी घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र खुलकर आलोचना करता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरिश ने गुरुवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में मानवाधिकारों के दमन और स्वतंत्रता पर अंकुश का जिक्र करते हुए कहा, 'अन्य देशों में इसी तरह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र कड़ी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे ऐसे दमन को वह ध्यान नहीं मिलता, जिसका वह हकदार है।'

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी घटनाक्रम पाकिस्तानी राज्य के वास्तविक चरित्र को पूरी तरह उजागर करते हैं।'

'विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तंत्र को मजबूत करने' के विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने का जवाब देते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरिश ने कहा, 'दुनिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता तथा मौलिक आजादी के लगातार हो रहे दमन की गवाह है।' उन्होंने कहा, 'ये कोई अलग-थलग मामले नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब आठ दशकों से पाकिस्तानी सरकार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।'

पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे कश्मीरियों को इस्लामाबाद सरकार ने बेरहमी से दबाया है। जून से अब तक कम से कम 34 कश्मीरी उसके सुरक्षा बलों द्वारा मारे जा चुके हैं।

हालिया घटना में 14 जुलाई को तरारखाल में पाकिस्तानी सेना ने छह कश्मीरियों को मार डाला। भारतीय प्रतिनिधि ने दमन के उदाहरणों में पूर्व प्रधानमंत्री समेत नेताओं को जेल में डालना और मुख्य विपक्षी पार्टी को गैरकानूनी घोषित करना बताया।

रुबियो के बयान पर ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने दी चेतावनी अमेरिकी आक्रामकता से बढ़ेंगी ट्रंप की मुश्किलें

विश्व केसरी

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के लगातार सैन्य हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित समझौता कोशिशों की कीमत और बढ़ा देंगे। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हालिया बयानों को जमीनी हकीकत से अलग बताते हुए खारिज कर दिया।

अराघची ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'अमेरिकी प्रशासन में समझौते की वकालत करने वाले लोग जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर केवल 2028 पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।'

उन्होंने कहा, 'वे जिस बिना सोचे-समझे सैन्य हमले की वकालत कर रहे हैं, उससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि ट्रंप को उस समझौते के लिए और अधिक कीमत चुकानी पड़े, जिसे हासिल करने की वह कोशिश कर रहे हैं।' अराघची की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस दावे के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान संघर्ष समाप्त करने के लिए वाशिंगटन के साथ निजी स्तर पर बातचीत करना चाहता है, हालांकि तेहरान फिलहाल किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। गुरुवार को मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रति 'आंख के बदले सिर' की नीति अपनाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जारी रही तो तेहरान को और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका की सेना ने गुरुवार शाम (स्थानीय समय) को ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों का एक और दौर शुरू किया। अमेरिकी सेना ने लगातार 13वीं रात को ईरान के ऊपर हमला जारी रखा।

कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

विश्व केसरी

ओंटारियो। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई अधिकारियों ने सीमा पार संचालित एक कथित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ओंटारियो में वजन के हिसाब से की गई सबसे बड़ी ड्रग जब्ती कार्रवाइयों में से एक के दौरान जांचकर्ताओं ने लगभग 14 करोड़ कनाडाई डॉलर मूल्य के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए और 21 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए।

पुलिस और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, 'प्रोजेक्ट बे' नामक इस अभियान के तहत लगभग 973 किलोग्राम संदिग्ध कोकीन, 660 किलोग्राम संदिग्ध मेथामफेटामाइन और 49 किलोग्राम संदिग्ध अफीम बरामद की गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने 230 ऑक्सीकोडोन की गोलियां, 17 आग्नेयास्त्र (जिनमें एक एंटी-टैंक राइफल भी शामिल है), भारी मात्रा में गोला-बारूद, प्रतिबंधित हथियार और उनसे संबंधित उपकरण भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने इसके अलावा महंगे आभूषण, नोट गिनने की मशीनें, 43 मोबाइल फोन, छह लैपटॉप, लगभग 80,000 कनाडाई डॉलर और 10,000 अमेरिकी डॉलर नकद भी बरामद किए। कथित अपराधों से जुड़ा एक वाहन भी जब्त किया गया। इस मामले की जांच जनवरी 2025 में विंडसर पुलिस ने शुरू की थी। इसके अगले महीने कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी जांच में शामिल हुई, ताकि कनाडा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कथित नेटवर्क की पहचान और जांच में सहायता मिल सके। जैसे-जैसे जांच प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक फैली, ओंटारियो प्रांतीय पुलिस भी इसमें शामिल हो गई। जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह गिरोह व्यावसायिक ट्रकिंग उद्योग में ब्रोकर-आधारित मॉडल के जरिए काम करता था और वैध परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता था।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में करेंगे अमेरिका का दौरा, व्हाइट हाउस में ट्रंप से होगी मुलाकात

विश्व केसरी

वाशिंगटन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में व्हाइट हाउस आने की उम्मीद है।

इससे व्यापार, तकनीक और सुरक्षा को लेकर रणनीतिक कॉम्पिटिशन के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के नेताओं के बीच एक और उच्चस्तरीय बैठक की योजना का संकेत मिलता है।

शी जिनपिंग के दौरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में 2025 वर्ल्ड सीरीज चैंपियन लॉस एंजिल्स डोजर्स की मेजबानी करते हुए कही। उन्होंने खिलाड़ियों को नए बने व्हाइट हाउस के मैदान और ओवल ऑफिस दिखाते हुए आने वाले दौरे का जिक्र किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'तीन हफ्ते पहले किंग चार्ल्स यहां आए थे। अगले तीन हफ्ते में राष्ट्रपति शी आ रहे हैं। वह सितंबर में यहां आने वाले हैं।'

उन्होंने कहा, 'हम दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस, ओवल ऑफिस से कुछ ही कदम दूर हैं, जहां सब कुछ शुरू होता है, खत्म होता है और शुरू होता है।'

ट्रंप ने कहा, 'हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली कार्यालय, ओवल ऑफिस से बस कुछ कदम दूर हैं। वहीं से सब कुछ शुरू होता है, खत्म होता है और फिर से शुरू होता है।' उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'बातचीत के लिए यह शानदार जगह है, क्योंकि जब लोग ओवल ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो वे थोड़ा असहज और भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे समय में उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए सबसे अच्छा मौका होता है।' हालांकि, ट्रंप ने प्रस्तावित बैठक, उसके एजेंडे या किसी संभावित समझौते के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना तो इंडो-पैसिफिक तक बढ़ेगा खतरा : रुबियो

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर ईरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण करने दिया गया तो यह एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। उनका कहना है कि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी ऐसा देखने को मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ क्षेत्रीय तनाव का नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों पर आजादी से आवाजाही और पूरी दुनिया की व्यापार व्यवस्था की सुरक्षा का है। मनीला में 'आसियान' पोस्ट-मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रुबियो ने कहा कि ईरान की हरकतें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एक बेहद अहम सिद्धांत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि एशिया के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। रुबियो ने कहा, 'ईरान यह अधिकार मांग रहा है कि वह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करे, लेकिन मौजूदा किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के तहत उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है।' उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग बताते हुए कहा कि अगर किसी देश को ऐसे रास्ते पर नियंत्रण करने दिया गया, तो इसके नतीजे सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे।

लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की अफ्रीकी संघ ने की निंदा, हूती समूहों से कार्रवाई रोकने की अपील

विश्व केसरी

अदीस अबाबा। अफ्रीकी संघ (एयू) ने गुरुवार को यमन के हूती समूह की ओर से लाल सागर में कमर्शियल तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। संघ ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई से तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है और इसका असर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर रूप से पड़ सकता है।

एक बयान में अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने सऊदी अरब के साथ पूरी एकजुटता जताई और देश की सुरक्षा, संप्रभुता और स्थिरता के लिए संघ के 'मजबूत समर्थन' को दोहराया।

यूसुफ ने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले करना और समुद्री यातायात की स्वतंत्र आवाजाही को रोकने की कोशिश करना अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्र में आने-जाने की आजादी और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि लाल सागर में समुद्री रास्तों की सुरक्षा अफ्रीका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस इलाके की सुरक्षा का सीधा असर कई देशों पर पड़ता है।

यूसुफ ने कहा, 'कमर्शियल जहाजों की आवाजाही में किसी भी तरह की रुकावट से क्षेत्रीय समुद्री संपर्क, दुनिया की सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और उन कई अफ्रीकी देशों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है, जिनका व्यापार इन सुरक्षित और लगातार चलने वाले समुद्री रास्तों पर निर्भर है।'

उन्होंने हूती समूह से अपील की कि वह 'तुरंत व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद करे, ऐसे किसी भी कदम से बचे जिससे तनाव और बढ़े, और समुद्री यातायात से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन करे।' इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हूती समूह जहाजों पर हमले जारी रखता है तो उसे और ईरान को 'बड़ी सैन्य कार्रवाई' का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा।

पुरी में बाहुड़ा यात्रा शुरू, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

विश्व केसरी

भुवनेश्वर। ओडिशा के पुरी में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा का शुभारंभ 'पहांडी बीजे' अनुष्ठान के साथ हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र, बहन देवी सुभद्रा और दिव्य आयुध चक्रराज सुदर्शन को भव्य शोभायात्रा के माध्यम से गुंडिचा मंदिर से उनके-अपने रथों तक लाया गया। इस दौरान लाखों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंचे।

बाहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के नौ दिनों के प्रवास के बाद गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर लौटने की पावन यात्रा है।

पहांडी बीजे अनुष्ठान के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवानों को गुंडिचा मंदिर (आड़प मंडप) से उनके रथों तक लाया गया। पूरे पुरी शहर में 'जय जगन्नाथ' और 'हरि बोल' के जयघोष गूंजते रहे।

मंदिर के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया, जबकि ओडिशी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते और नृत्य करते नजर आए। परंपरा के अनुसार, देवताओं के रथों पर विराजमान होने के बाद पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव स्वर्ण झाड़ू से रथों की प्रतीकात्मक सफाई करेंगे। इस रस्म को 'छेरा पहंरा' कहा जाता है। इसके बाद श्रद्धालु गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक तीनों रथों को खींचेंगे। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन सभी धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारु रूप से संपन्न कराने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

ओडिशा पुलिस ने बाहुड़ा यात्रा, 'सुना बेशा' समेत अन्य प्रमुख अनुष्ठानों को देखते हुए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। केंद्रीय रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सत्यजीत नाइक ने बताया कि भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, रथ खींचने की व्यवस्था, रात्रि गश्त और तटीय सुरक्षा के लिए 223 पुलिस बलों की तैनाती की गई है।

उन्होंने कहा कि इस बार बहुदा यात्रा और सुना बेशा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। आईजीपी के अनुसार, शुक्रवार को बहुदा यात्रा के दौरान करीब सात लाख श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने का अनुमान है। वहीं शनिवार को होने वाले 'सुना बेशा' अनुष्ठान के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

फर्जी खबर फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, केरल सीएम ने दिए आदेश

विश्व केसरी

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सीपीआई(एम) की केंद्रीय समिति की सदस्य और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पी.के. श्रीमती के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए कथित फर्जी प्रचार अभियान पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ने उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को एक औपचारिक शिकायत सौंपी थी। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह झूठा दावा किया गया कि उन्होंने विधायक परिवार पेंशन धोखाधड़ी से प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने शिकायत मिलते ही इसे राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को भेजते हुए मामले में तत्काल और उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सरकारी हस्तक्षेप के बाद जांच में सामने आया

कि यह मामला नाम की समानता के कारण पैदा हुई गलतफहमी का था। जिस पेंशन का जिक्र किया जा रहा था, वह सीपीआई(एम) नेता पी.के. श्रीमती को नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता पी.आर. कृष्णन की दिवंगत पत्नी पी.के. श्रीमती को मिलती थी। पी.आर. कृष्णन पूर्व त्रावणकोर-कोचीन विधानसभा और बाद में कुन्नमकुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे।

थ्रिसूर के पूचट्टी स्थित ए.के.एम. हायर सेकेंडरी स्कूल की सेवानिवृत्त शिक्षिका रही पी.के. श्रीमती को वर्ष 1993 में अपने पति के निधन के बाद विधानसभा की पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। फरवरी 2020 में उनके निधन के बाद यह पेंशन बंद कर दी गई।

उनके बेटे अजीत (प्रिंटेक्स अजीत) ने स्पष्ट किया कि पिछले छह वर्षों से किसी ने भी यह पेंशन प्राप्त नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का नाम बेवजह विवाद में घसीटा गया और संभव है कि सीपीआई(एम) नेता को या तो नाम समान होने के कारण निशाना बनाया गया या फिर जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई।

आरटीआई के जवाब को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया

यह विवाद पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े आरटीआई के जवाब के बाद शुरू हुआ। दस्तावेज में एक ओर 'पी.के. पत्नी पी.आर. कृष्णन' को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का उल्लेख था, जबकि दूसरी ओर कन्नूर की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पी.के. श्रीमती की पेंशन संबंधी अलग जानकारी दर्ज थी।

संक्षिप्त खबर

सूरत में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

विश्व केसरी

सूरत। गुजरात के सूरत जिले में हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अब तक 2,900 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों और जलाशयों के आसपास जाने से बचने की अपील की है, जबकि राहत एवं बचाव के लिए एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन के डिप्टी मामलतदार साजिद मेरुजय ने आईएएनएस को बताया कि 24 जुलाई दोपहर 12 बजे तक की स्थिति के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूरे सूरत जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि, शुक्रवार सुबह 8 बजे के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 24 जुलाई के लिए सूरत जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि फ्लैश फ्लड की चेतावनी के तहत 25 जुलाई सुबह 5:30 बजे तक कई स्थानों पर जलभराव और पानी भरने की आशंका जताई गई है। नाउकास्ट के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी येलो अलर्ट प्रभावी रहा। उन्होंने बताया कि जिले की मांडवी तहसील स्थित केवड़ी और लाखी बांध हाई अलर्ट पर हैं। वहीं, उकाई बांध से फिलहाल 800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि बांध में लगभग 84 हजार क्यूसेक पानी की आवक हो रही है।

मुख्यमंत्री ने सीईओ को कर्नाटक के विकास के भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया

विश्व केसरी

बेंगलुरु। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को उद्योग जगत के नेताओं से कर्नाटक सरकार के साथ राज्य के विकास के अगले चरण को आकार देने में साझेदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने बेंगलुरु से परे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विस्तार, उद्योग की भागीदारी से एक एआई विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की। सीईओ की एक बैठक को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रतिभा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है, और शहर की सफलता का श्रेय उन लोगों और कंपनियों को दिया जिन्होंने इसे भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी बनाया है। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से कहा कि आप बेंगलुरु के राजदूत हैं। आप कर्नाटक के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कई लोग दशकों पहले शहर में आए थे, लेकिन उन्होंने शहर द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और प्रतिभा के कारण यहीं रहने का विकल्प चुना। कर्नाटक के आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर निर्यात 43 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और इस वर्ष इसके 55 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है।

बारामूला पुलिस ने ड्रग तस्करी में शामिल गाड़ी जब्त की, आम लोगों से पुलिस को सूचना देने की अपील

विश्व केसरी

बारामूला। जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारामूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामले में शामिल एक वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बारामूला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में की गई है। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने टाटा पंच गाड़ी को जब्त किया है। बारामूला पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने के लिए केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के जरिए अर्जित संपत्तियों और अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करना भी जरूरी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से ड्रग तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर दबाव बढ़ेगा। पुलिस ने दोहराया कि जिले में ड्रग्स से जुड़े अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म कर एक सुरक्षित और नशा मुक्त समाज बनाना है। बारामूला पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध ड्रग गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और समाज को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाया जा सके।

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, सबूत नहीं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या मतलब

विश्व केसरी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि जांच एजेंसियां अदालत में पर्याप्त सबूत ही पेश नहीं करेंगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आश्वासन केवल दिखावा साबित हो रहा है।

केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए संसद में कानून लाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन उनके अनुसार, इसी बीच वर्ष 2024 के नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अदालत में कथित तौर पर यह कहे जाने से कि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप प्रमुख ने दावा किया कि वर्ष 2024 में नीट पेपर लीक के समय सरकार ने संजीव मुखिया को पूरे मामले का मास्टरमाइंड

बताया था और बड़े स्तर पर उसकी गिरफ्तारी को उपलब्धि के रूप में पेश किया गया था। हालांकि अब यदि सीबीआई अदालत में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की बात कह रही है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आखिर इस मामले का वास्तविक मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने सवाल किया कि यदि वही मास्टरमाइंड नहीं है, तो क्या सरकार यह मान रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं? केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि यदि जांच एजेंसियां अदालत में मजबूत सबूत पेश नहीं करेंगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि वास्तविक कार्रवाई के स्तर पर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।

ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेने के आरोप में दो मोटर वाहन निरीक्षक निलंबित, सीएम का सख्त संदेश

विश्व केसरी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेने के आरोप में दो मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को निलंबित कर भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पश्चिम बर्धमान जिले के रामपुर चेक पोस्ट पर तैनात दो एमवीआई को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने जरूरी कागजात होने के बाद भी एक ट्रक ड्राइवर से रिश्वत मांगी और उसे बेवजह परेशान किया।

राज्य की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा, 'कानून से ऊपर कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार प्रशासन, विभागों और सरकार के हर स्तर पर

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। किसी भी स्थिति में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हम अपने प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाने और भ्रष्ट तत्वों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'घटना और शिकायत का विवरण: सामान ढोने वाला ट्रक नंबर जेएच09बीए3535 (मालिक: दीपक सिंह, चालक: शिवा यादव) सर्विसिंग के बाद गैराज लौट रहा था। इस दौरान पश्चिम बर्धमान के रामपुर चेक पोस्ट पर अधिकारियों ने उसे गलत तरीके से रोक लिया। आरोप है कि चालक को अवैध रूप से परेशान किया गया और रिश्वत देने का दबाव बनाया गया। रिश्वत देने से इनकार करने पर वाहन को जब्त कर लिया गया और ऐसे टैक्स के नाम पर 22,000 रुपए की अवैध मांग की गई, जिसे राज्य सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है।' जिन दो मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को निलंबित किया गया है और जिनके खिलाफ एसीबी ने जांच शुरू की है, उनकी पहचान नजीमुल हक और अनुपम बनर्जी के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'शिकायतों को पूरी आपराधिक जांच और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को भेज दिया गया है।

कालीघाट में बिल्डिंग नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के पिता को किया तलब

विश्व केसरी

कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को एक नोटिस जारी किया। इसमें दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में मौजूद दो रिहायशी संपत्तियों पर कथित तौर पर बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस नोटिस में अमित बनर्जी को केएमसी के बोरो 11 ऑफिस के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सामने उन दो प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी कागजात के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और यह साफ नहीं है कि वह बताए गए निर्देश के अनुसार सिविक बॉडी के सामने पेश होंगे या नहीं। अमित बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई हैं। कॉरपोरेशन पहले से ही

कालीघाट में बनर्जी परिवार से जुड़ी अलग-अलग प्रॉपर्टी के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है, खासकर यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्माण केएमसी के नियमों के अनुसार किया गया था या नहीं। अधिकारियों के अनुसार, जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या प्रॉपर्टी पर निर्माण मंजूर किए गए स्पेसिफिकेशन से ज्यादा था या मंजूर बिल्डिंग प्लान से अलग था।यह घटनाक्रम कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के आवास के हालिया निरीक्षण के बाद हुआ है। घर के सदस्यों को भी नोटिस भेजे गए थे। इसके बाद, अमित बनर्जी और उनकी पत्नी लता बनर्जी ने सिविक बॉडी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि दोनों प्रॉपर्टी का निर्माण केएमसी के बिल्डिंग नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए किया गया था और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था।

अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री शर्मा के पेपर लीक के दावे को चुनौती दी

विश्व केसरी

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस दावे को चुनौती दी कि उनकी सरकार के पिछले ढाई वर्षों के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था।

एक बयान में, गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षाओं से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने में विफल रही है। नीट-यूजी परीक्षा का जिक्र करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि लीक से संबंधित शिकायतों को शुरू में राज्य सरकार और पुलिस द्वारा दबा दिया गया था

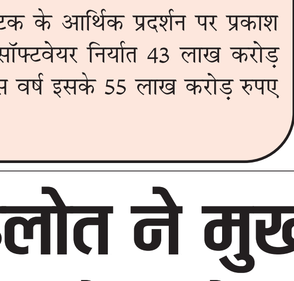

और यह मामला तभी सामने आया जब छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से संपर्क किया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कई अन्य कथित अनियमितताओं का भी हवाला दिया, जिनमें नवलगढ़ (झुंझुनू) में एक बिना सील वाले लिफाफे में आरएएस परीक्षा का पेपर बरामद होना, एक लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर कथित तौर पर टूटी हुई सील के साथ आना, जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के आरोप और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसबी) के एक तकनीकी प्रमुख से जुड़े ओएमआर शीट में हेराफेरी का मामला शामिल है। गहलोत ने आगे कहा कि हालांकि भाजपा सरकार ने बाद में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन उसने शुरू में राजस्थान हाई कोर्ट में इसका विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई की गई।

एनडीआरएफ ने 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला, राहत एवं बचाव अभियान जारी

विश्व केसरी

गुवाहाटी। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुक्रवार को भी राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने अपने फ्लड वाटर रेस्क्यू (एफडब्ल्यूआर) अभियान को और तेज कर दिया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एनडीआरएफ की टीमों ने अब तक 59 लोगों को बचाया, 4,037 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, 48 मवेशियों का भी सफलतापूर्वक बचाव किया तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से छह शव बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें उन संवेदनशील जिलों में तैनात हैं, जहां

नदियों के उफान और जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बचाव दल नावों और विशेष उपकरणों की मदद से चौबीसों घंटे राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से राहत एवं निकासी अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'प्रभावित इलाकों में राहत और निकासी अभियान विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से लगातार जारी है। एनडीआरएफ के जवानों की अटूट प्रतिबद्धता और सेवा भावना सराहनीय है। उन्होंने एनडीआरएफ के ताजा अभियान से जुड़े आंकड़े भी साझा किए और बाढ़ प्रभावित जिलों में चल रहे व्यापक राहत कार्यों की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, एनडीआरएफ के अलावा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय स्वयंसेवक भी बचाव अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

एक्स-रे देखकर शुरू कर दी टीबी की दवा, बाद में निकली दूसरी बीमारी, विशेषज्ञों ने दी सावधानी की सलाह

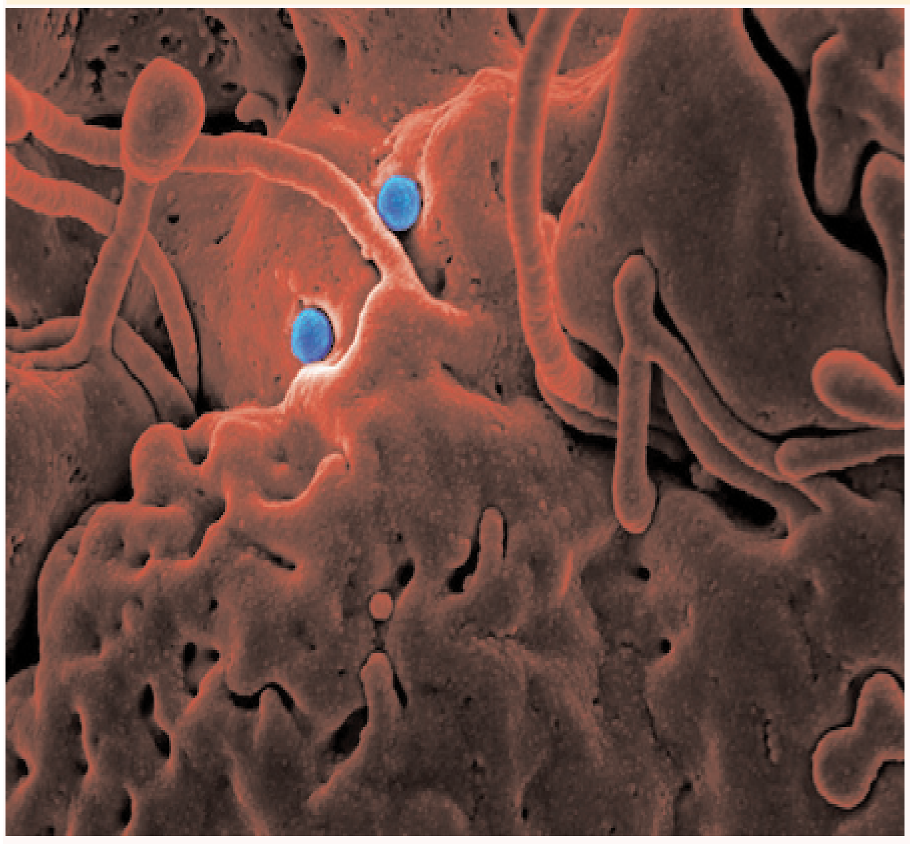

विश्व केसरी ■

लखनऊ। केवल एक्स-रे और सामान्य लक्षणों के आधार पर टीबी (क्षय रोग) का इलाज शुरू करना मरीजों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। राजधानी के सिविल अस्पताल में रोज ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां टीबी की पुष्टि किए बिना मरीजों को उसकी दवाएं दी जा रही हैं, जबकि कई वास्तविक टीबी मरीज दूसरी बीमारियों का इलाज कराते रहते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि टीबी की सही पहचान के लिए एक्स-रे के साथ बलगम जांच, सीबी-नॉट (सीबीएनएएटी), जीन एक्सपर्ट, सीटी स्कैन और मरीज की चिकित्सीय पृष्ठभूमि का मूल्यांकन जरूरी है।

राजधानी के अहिमामऊ निवासी 46 वर्षीय प्रेमचंद को लगातार खांसी, सांस फूलने और वजन घटने की शिकायत पर एक निजी चिकित्सक ने एक्स-रे में धब्बे देखकर टीबी की दवा शुरू कर दी। एक सप्ताह तक दवा लेने के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ।

बाद में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में विस्तृत जांच के दौरान पता चला कि उन्हें टीबी नहीं, बल्कि फेफड़ों में गांठ (लंग नोड्यूल) की समस्या है। इसके बाद टीबी की दवा बंद कर दी गई। सिविल अस्पताल के वरिष्ठ क्षय रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष दुबे के अनुसार, एक्स-रे में दिखाई देने वाला हर धब्बा टीबी का कारण नहीं होता। फेफड़ों का कैंसर, गांठ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और टीबी के एक्स-रे कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं। लगभग 30 प्रतिशत मामलों में केवल एक्स-रे के आधार पर किया गया आकलन गलत साबित होता है। इसलिए जरूरी जांच के बाद टीबी की पुष्टि होने पर ही इलाज शुरू किया जाना चाहिए।

डॉ. दुबे ने बताया कि सिविल अस्पताल में हर महीने 150 से 200 नए टीबी मरीज और 2 से 3 मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर) टीबी के मामले सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 15 से 17 हजार एमडीआर टीबी के मरीज मिलते हैं। हालांकि समय पर पहचान, जांच और इलाज के कारण टीबी से ठीक होने की दर अब 90 प्रतिशत अधिक हो चुकी है और प्रति लाख आबादी पर मरीजों की संख्या भी घटकर 200 से नीचे पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि एक अनुपचारित टीबी मरीज प्रतिवर्ष 15 अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। यदि मरीज बीच में दवा छोड़ देता है

तो एमडीआर टीबी विकसित हो सकती है। एमडीआर का इलाज भी अधूरा छोड़ दिया जाए तो एक्सडीआर टीबी जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका इलाज करीब दो वर्ष तक चलता है।

क्षय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि टीबी का जीवाणु चार्ल्स डार्विन के 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' सिद्धांत पर काम करता है। मतलब बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना। उन्होंने बताया कि टीबी के जीवाणु चार तरह के होते हैं।

बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी, दो बच्चों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 805 पहुंचा

विश्व केसरी ■

ढाका। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी है। गुरुवार को इस बीमारी जैसे लक्षणों वाले दो और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 805 हो गई है।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के मुताबिक, गुरुवार सुबह तक के पिछले 24 घंटों में ये दो मौतें दर्ज की गईं। बांग्लादेशी समाचार एजेंसी 'यूएनबी' के अनुसार, इन दोनों मौतों को फिलहाल संदिग्ध खसरे से हुई मौत माना गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, खसरे से हुई पुष्टि की गई मौतों की संख्या अभी भी 95 है, लेकिन संदिग्ध मौतों का आंकड़ा बढ़कर 710 हो गया है।

डीजीएचएस ने पिछले 24 घंटों में खसरे के 848 नए संदिग्ध मामले दर्ज किए। इसके साथ ही 15 मार्च से अब तक संदिग्ध मामलों की कुल संख्या 1,21,200 हो गई है।

इसी दौरान खसरे के 166 नए पुष्टि किए गए मामले भी सामने आए, जिससे कुल पुष्टि किए गए मामलों की संख्या बढ़कर 15,007 हो गई।

बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खसरे से हर दिन औसतन लगभग चार बच्चों की मौत हो रही है और रोज 800 से ज?यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। वहीं, सरकार की कोशिशें और लोगों का ध्यान दोनों पहले की तुलना में कम होते दिख रहे हैं।

सरकार का कहना है कि उसने आपातकालीन खसरा टीकाकरण अभियान का लक्ष्य पूरा कर लिया है, लेकिन अस्पतालों में अब भी बिना टीका लगवाए मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे साफ है कि टीकाकरण का दायरा अभी भी पर्याप्त नहीं है।

जुलाई के पहले तीन हफ्तों में भी हालात गंभीर बने रहे। डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान हर दिन औसतन 1,005 संदिग्ध और पुष्टि किए गए मामले सामने आए, 821 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और लगभग चार लोगों की मौत हुई।

बांग्लादेश की प्रमुख अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, खसरा और रूबेला खत्म के लिए बनी नेशनल वेरिफिकेशन कमेटी के अध्यक्ष महमूदुर रहमान ने कहा, 'हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन टीकाकरण अभियान शुरू होने के दो महीने बाद जितना सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। लगता है कि अधिकारी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं।'

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रकोप इसलिए लगातार बना हुआ है ।

गूगल पर यूरोपीय संघ का बड़ा एक्शन, डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन पर लगाया 1 अरब डॉलर का जुर्माना

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ (ईयू) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में गूगल पर कुल 89 करोड़ यूरो (करीब 1 अरब डॉलर) का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग का आरोप है कि गूगल ने अपने सर्च प्लेटफॉर्म पर अपनी ही सेवाओं को प्राथमिकता दी और अपने ऐप इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया।

यूरोपीय आयोग ने गूगल की सर्च से जुड़ी गतिविधियों के लिए 46 करोड़ यूरो और गूगल प्ले स्टोर के नियमों से जुड़े मामले में 43 करोड़ यूरो का अलग-अलग जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को 60 दिनों के भीतर आदेशों का पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर गूगल पर उसकी वैश्विक कुल आय का 5 प्रतिशत तक

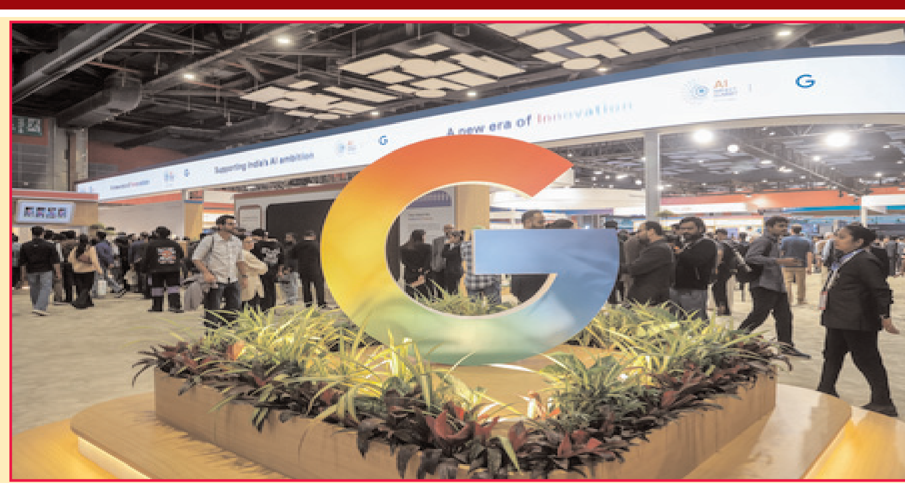

अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

आयोग ने अपने बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि गूगल अपने सर्च प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स जैसी अपनी सेवाओं को तीसरे पक्ष की सेवाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। यह डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) के तहत तय नियमों का उल्लंघन है।

यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरा ने कहा कि गूगल डिजिटल मार्केट्स एक्ट के प्रभावी अनुपालन में विफल रहा है। इसलिए आयोग ने संतुलित लेकिन सख्त कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर सफल होना चाहिए, न कि इसलिए कि वे उसी कंपनी के हैं जो सर्च इंजन संचालित करती है।

आयोग के अनुसार, डीएमए के तहत गूगल प्ले के जरिए अपने ऐप वितरित करने वाले डेवलपर्स को ग्राहकों को वैकल्पिक और अक्सर सस्ते विकल्पों की जानकारी मुफ्त में देने तथा उन्हें वेबसाइट या अन्य ऐप स्टोर के जरिए खरीदारी करने के लिए स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति होनी चाहिए।

दवा कंपनियों की मार्केटिंग पर लागू किए गए नए सख्त नियम, डॉक्टरों को गिफ्ट और नकद लाभ देने पर रोक: सरकार

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों की मार्केटिंग में पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी), 2024 के तहत कई सख्त प्रावधान लागू किए हैं।

नए नियमों के तहत दवा कंपनियों को एथिक्स कमेटी फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (ईसीपीएमपी) का गठन करना होगा, एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करना होगा, शिकायतों के निपटारे और अपील की व्यवस्था करनी होगी, नियमों के पालन का स्व-घोषणा पत्र देना होगा और निर्धारित मार्केटिंग खर्च का खुलासा भी करना होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को संसद में दी गई।

सरकार ने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर रोक लगाना और दवाओं के जिम्मेदार प्रचार को बढ़ावा देना है, जिसके तहत डॉक्टरों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाले संपर्क और प्रचार गतिविधियों को भी विनियमित किया गया है।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि फार्मास्युटिकल्स विभाग ने 12 अप्रैल 2024 को यूसीपीएमपी, 2024 अधिसूचित किया था, जिसने यूसीपीएमपी, 2015 की जगह ली। इसके बाद सितंबर 2025 में इस कोड में संशोधन भी किया गया।

उन्होंने बताया कि यूसीपीएमपी, 2024 में दवा कंपनियों द्वारा नैतिक मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें ईसीपीएमपी का गठन, एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति, शिकायतों के निपटारे और अपील की दो-स्तरीय व्यवस्था, नियमों के पालन से संबंधित स्व-घोषणा और निर्धारित मार्केटिंग खर्च का खुलासा शामिल है।

मंत्री ने कहा कि इस कोड में दवा कंपनियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच प्रचार गतिविधियों से जुड़े नियमों को भी और मजबूत बनाया गया है। वर्ष 2025 में किए गए संशोधनों के तहत कंपनियों को संबंधित पोर्टल पर हर साल अपने मार्केटिंग खर्च का विवरण भी जमा करना अनिवार्य किया गया है।

सरकार के अनुसार, इस कोड का मुख्य उद्देश्य दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर रोक लगाना और डॉक्टरों के बीच दवाओं के प्रचार को जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करना है।

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिटेल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 28.6 प्रतिशत बढ़ी: रिपोर्ट

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सभी सेगमेंट में रिटेल बिक्री जुलाई में अब तक (1-23 जुलाई) सालाना आधार पर 28.6 प्रतिशत बढ़ी है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, दोपहिया वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एसयूवी और पैसेंजर कार सेगमेंट में मजबूत मांग के चलते यात्री वाहनों की बिक्री 20.6 प्रतिशत बढ़ी।

रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 27.3 प्रतिशत और तीनपहिया वाहनों की बिक्री में 18.1 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैक्टर सेगमेंट में भी 36.8 प्रतिशत की मजबूत सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली।

रिपोर्ट में कहा गया, 'हमें उम्मीद है कि जुलाई

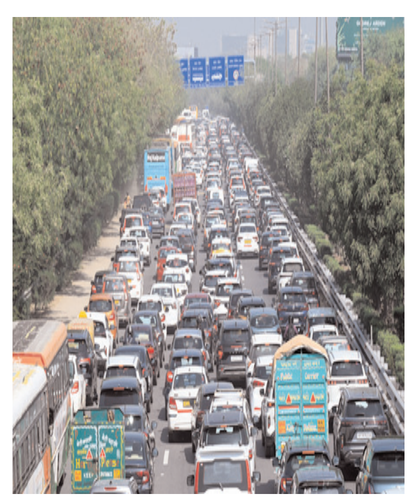

2026 में ऑटो उद्योग मजबूत वृद्धि दर्ज करेगा। इसके पीछे जुलाई 2025 का कम बेस, उपभोक्ता भावना में स्थिरता, हाल में लॉन्च हुए नए मॉडल, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जाना, ब्याज दरों में नरमी और जीएसटी कटौती बाद बढ़ी खरीदने की क्षमता जैसे प्रमुख कारण हैं।'

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आने वाले महीनों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक है। इसकी वजह मजबूत मांग, अगस्त-सितंबर 2026 का कम बेस और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के दूसरे हिस्से में त्योहारों के कारण मांग में आने वाली तेजी है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से जुलाई महीने के आखिरी आठ दिनों में पूरे महीने की कुल बिक्री का लगभग 25-28 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया जाता है।

एक अन्य हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ऑटो और ऑटो एंसिलरी क्षेत्र का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र नए निवेश चक्र में प्रवेश कर रहा है, जहां वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2028-29 के बीच 70,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होने की संभावना है।

तनावमुक्त जीवन और बेहतर एकाग्रता के लिए करें उत्थित पार्श्वकोणासन योगासन

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। आज की व्यस्त जीवनशैली में शारीरिक संतुलन और आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। ऐसी स्थिति में उत्थित पार्श्वकोणासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर को ताजगी प्रदान करता है।

उत्थित का अर्थ है, खिंचाव, पार्श्व का अर्थ बगल और कोण का अर्थ एंगल हैं। यह एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर के पार्श्व (साइड) भाग में एक संपूर्ण और सुंदर पार्श्व-कोण बनता है। यह न केवल हमारी शारीरिक शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है, बल्कि मन में स्थिरता और एकाग्रता भी लाता है।

आयुष मंत्रालय के अनुसार, उत्थित पार्श्वकोणासन (विस्तारित पार्श्व कोण मुद्रा) खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक आसन है, जो पेट के अंगों की मालिश करता है, पाचन में सुधार लाता है, और पैरों व रीढ़ को मजबूत करता है। इसके अलावा, शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, यह छाती के विकास और साइटिका के दर्द में राहत दिलाता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति साइटिका से ज्यादा परेशान है, तो वे सबसे पहले डॉक्टर से सलाह करें।

इसको करना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले योगा मैट पर दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैला लें। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुटने से धीरे-धीरे मोड़ें और उसी मुद्रा में नीचे की ओर बैठें। फिर अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पास जमीन पर रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा 90 डिग्री के एंगल में रखने की कोशिश करें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने की कोशिश करें, फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। हालांकि, शुरुआती अभ्यासकर्ताओं को इसको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी और शरीर खुलने लगेगा। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ (बाएं पैर को मोड़कर) दोहराएं।

गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं के लिए फायदेमंद है व्यायाम, डिप्रेशन और एंग्जायटी होगी कम

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। गर्भावस्था और प्रसव के बाद का समय महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण दौर होता है। इस दौरान जहां एक ओर मां बनने की खुशी होती है, वहीं दूसरी ओर शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, थकान, पर्याप्त नींद न मिलना और नवजात की देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाओं को तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि इस दौरान नियमित शारीरिक गतिविधि और हल्का व्यायाम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है।

'फिजिकल एक्टिविटी एंड पेरिनेटल डिप्रेशन एंड एंग्जायटी: अ ग्लोबल अम्ब्रेला रिव्यू' शीर्षक से प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था और प्रसव के आसपास के समय में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने वाली महिलाओं में अवसाद और चिंता के लक्षण अपेक्षाकृत कम देखे गए। शोधकर्ताओं के अनुसार, नियमित शारीरिक गतिविधि मानसिक तनाव कम करने का एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकती है।

यह अध्ययन दुनिया भर में प्रकाशित कई पूर्व अध्ययनों की समीक्षा पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2014 से अप्रैल 2026 तक प्रकाशित अध्ययनों का विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने पबमेड, एम्बेस, वेब ऑफ साइंस, कोक्रेन लाइब्रेरी, साइकोइन्फो समेत कई अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा डेटाबेस से जानकारी जुटाई। कुल 4,109 अध्ययनों की समीक्षा के बाद 20 प्रमुख अध्ययनों को विश्लेषण में शामिल किया गया, जिनमें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान या बाद में शारीरिक गतिविधि का अवसाद और चिंता पर प्रभाव जांचा गया था।

अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से महिलाओं में अवसाद के लक्षण कम हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद हल्का व्यायाम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और सकारात्मक मनोदशा बनाए रखने में सहायक हो सकता है।अध्ययन में योग को भी लाभकारी बताया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, योग तनाव कम करने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है।

यूथ हॉकी5एस एशियन चैंपियनशिप: भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को दी मात, महिला टीम ने कजाकिस्तान को 10-0 से रौंदा

विश्व केसरी

मस्कट (ओमान)। ओमान में चल रही एफआईएच यूथ हॉकी5एस एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय सब-जूनियर महिला और पुरुष टीमों ने गुरुवार को बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने-अपने एलीट पूल में अजेय रहने का सिलसिला जारी रखा। महिला टीम ने कजाकिस्तान पर 10-0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 8-3 से हराया।

भारतीय महिला टीम ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की। नौशीन नाज ने पहले ही मिनट में दो गोल किए और भारतीय टीम को अहम बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं संदीप कुमारी (11वें, 16वें, 18वें मिनट में तीन गोल दागते हुए हैट्रिक लगाई, जबकि नौशीन ने पहले ही हाफ में भारत की ओर से चार गोल किए। किरण एक्का (15वें मिनट), नीलम टोपनो (17वें मिनट) और पुष्पा मांझी (19वें मिनट) ने भी एक-एक गोल करते हुए भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान निभाया। भारतीय पुरुष टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाफ मैच का पहला हाफ काफी कड़ा मुकाबला रहा। कप्तान और 'प्लेयर ऑफ द मैच' केतन कुशवाहा (4वें, 8वें मिनट) और शाहरुख अली (3वें मिनट) के गोल की बदौलत भारत 3-2 से आगे था। हालांकि, मो. होसेन (6वें मिनट) और सोहराब सोटोन (8वें मिनट) के गोल ने बांग्लादेश को भारत के करीब बनाए रखा।

भारत ने दूसरे हाफ में कुशवाहा के दो और गोल तथा रोमित पाल, प्रहलाद राजभर और राहुल यादव के एक-एक गोल के साथ अपनी बढ़त बढ़ाई।

इस दौरान बांग्लादेश केवल एक और गोल कर सका, जिसमें सोटोन ने अपना दूसरा गोल (ब्रेस) पूरा किया। महिला टीम अब चीन और उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जबकि पुरुष टीम 24 जुलाई को ओमान और पाकिस्तान का सामना करेगी। यह टूर्नामेंट पहली बार होने वाले एफआईएच यूथ हॉकी5एस वर्ल्ड कप के लिए एशियाई क्वालीफायर भी है।

इससे पहले, सोमवार को भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की।

'एक बिहारी सब पर भारी होना शुरू हो चुका है', आकाश चोपड़ा हुए वैभव की आतिशी बल्लेबाजी के मुरीद

विश्व केसरी

नई दिल्ली। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर चला। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी वैभव की आतिशी बैटिंग के कायल हो गए हैं। उन्होंने इस युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है।

आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में वैभव द्वारा खेले गए शॉट्स की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी में कितना दमखम है यह जानने के लिए उनके बल्ले से निकले वो तीन शॉट्स ही काफी थे। पहला वो रिचर्ड नगारवा की गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। उसके बाद आगे की गेंद पर बिना पैर चलाए वैभव ने हाथों की मदद से कवर्स की तरफ से शानदार चौका लगाया। फिर जब उन्हें थोड़ी छोटी और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिली, तो उन्होंने बैकफुट पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया।'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वैभव ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही काफी कुछ देख लिया है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया, फिर टीम से ड्रॉप हुए और अब शानदार वापसी भी कर ली है। इसके साथ ही वैभव ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक भी लगा दिया है। आकाश ने वैभव को खास टैलेंट बताया। उन्होंने कहा कि वैभव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते गेंदबाज को एक ही जगह पर गेंदबाजी करने की इजाजत ही नहीं देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आकाश ने कहा, 'एक बिहारी सब पर भारी होना शुरू हो चुका है।'

वैभव ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 4 चौके और चार छक्के लगाए।

लुका मोड्रिक ने एक साल के लिए बढ़ाया एसी मिलान संग अपना करार

विश्व केसरी

मिलान। क्रोएशिया के दिग्गज फुटबॉलर लुका मोड्रिक ने अपने शानदार खेल करियर को एक और साल आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने इटली के क्लब एसी मिलान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिया है। क्लब ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है।

मोड्रिक अब 30 जून 2027 तक एसी मिलान के साथ जुड़े रहेंगे। सितंबर में 41 साल के होने जा रहे मोड्रिक ने पिछले साल रियल मैड्रिड के साथ 13 साल का सफल सफर खत्म करने के बाद मिलान का दामन थामा था। एसी मिलान के साथ उनका पिछला करार 30 जून को समाप्त हो गया था।

अपने पहले सीजन में मोड्रिक ने एसी मिलान के लिए 37 मुकाबले खेले और दो गोल किए। हालांकि, टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मिलान सेरी ए में पांचवें स्थान पर रहा और कोपा इटालिया में टीम अंतिम-16 दौर तक ही पहुंच सकी। मोड्रिक ने पहले कहा था कि वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगे। हालांकि, अब उन्होंने क्लब फुटबॉल में अपना सफर जारी रखने का फैसला किया है।

क्रोएशिया की टीम वर्ल्ड कप में पुर्तगाल से हारकर राउंड ऑफ-32 से बाहर हो गई थी। एसी मिलान ने अपने बयान में कहा कि मोड्रिक ने एक और सीजन के लिए क्लब के साथ नया करार किया है। क्लब ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मिडफील्ड में आने के बाद से मोड्रिक ने अपने अनुभव, मेहनत और खेल कौशल से टीम को मजबूती दी है। वह नए सीजन में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे।

2018 में बैलन डी'ओर जीतने वाले मोड्रिक अगले सीजन में भी एसी मिलान की नंबर-14 जर्सी पहनेंगे। मोड्रिक ने 2012 में इंग्लैंड के क्लब टोटेनहम हॉटस्पर से रियल मैड्रिड का रुख किया था।

आईएसएसएफ विश्व कप: संयम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता

विश्व केसरी

हांगझोऊ०। भारतीय शूटर संयम ने शुक्रवार को आईएसएसएफ विश्व कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक से विश्व कप में भारत के पदकों का खाता खुला। संयम ने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर पदक जीता। संयम के करियर का यह दूसरा आईएसएसएफ विश्व कप पदक है।

पूर्व जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन संयम ने क्वालीफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, और पोडियम फिनिश पक्का करने के लिए फाइनल फायरिंग लाइन पर कदम रखने से पहले अपनी सीरीज में लगातार प्रिसिजन बनाए रखा।

इवेंट में शामिल 36 सदस्यों वाला भारतीय दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन के व्यक्तिगत और मिश्रित-टीम इवेंट्स दोनों में मुकाबला करेगा। निशानेबाजों में मनु और स्वप्निल के साथ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह,

सुरुचि, एलावेनिल वलारिवन, सिफ्ट कौर समरा, सोनम उत्तम मस्कर, अनीश भानवाला, रायजा ढिल्लों, गनेमत सेखों और ओलंपियन अनंत जीत सिंह नरुका जैसे जाने-माने नाम हैं।

राइफल इवेंट्स में, पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लों, शाहू तुषार माने और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पाडेकर को महिलाओं के मुकाबले के लिए चुना गया है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्रांक्श बालासाहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं के इवेंट में आशी चौकसे, विदरसा के. विनोद और सिफ्ट कौर समरा हिस्सा लेंगी।

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के पिस्टल कैंपेन की अगुआई सुरुचि, संयम और ईशा सिंह करेंगी, जबकि पुरुषों के इवेंट में केदारलिंग बी. उचागंवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल होंगे।

आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप: विमेंस स्कीट इवेंट में किम्बर्ली रोड का जलवा, 27वें वर्ल्ड कप गोल्ड पर निशाना साधा

विश्व केसरी

हांगझोऊ। तीन बार की ओलंपिक चैंपियन किम्बर्ली रोड ने अपना 27वां वर्ल्ड कप खिताब जीता। गुरुवार को हांगझोऊ में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के दौरान महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में अमेरिका ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया।

47 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने फाइनल में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और अपनी टीम की साथी सामंथा सिमोंटन को 34-32 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। यह उनका 41वां वर्ल्ड कप मेडल था।

चीन की चे युफेई ने 28 हिट के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। 27 वर्षीय निशानेबाज का यह शूटिंग वर्ल्ड कप में दूसरा पदक है। वहीं, क्वालिफिकेशन में 123 हिट के साथ शीर्ष पर रहने वाली और पेरिस 2024 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता जियांग यीटिंग टाईब्रेकर में हारने के बाद पांचवें स्थान पर रहीं, जबकि उनकी हमवतन जियांग चाओयू सातवें स्थान पर रहीं।

दिन के दूसरे सत्र में जियांग यीटिंग के पेरिस 2024 ओलंपिक मिश्रित टीम स्पर्धा के साथी ल्यू जियानलिन ने पुरुष स्कीट स्पर्धा में 29 हिट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चीन की झोली में एक और पदक डाला।

विमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस स्पर्धा में ब्रिटेन की सियोनाइड मैकिंटोश ने बेहद रोमांचक फाइनल में चीन की हान जियायु को मात्र 0.3 अंकों के करीबी से हराकर गोल्ड अपने नाम किया।

हान जियायु ने 'नीलिंग' और 'प्रोन' दोनों चरणों के बाद बढ़त बना रखी थी, लेकिन स्टैंडिंग चरण में मैकिंटोश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 362.6 अंक हासिल किए और 362.3 अंक पर रहीं हान को मामूली अंतर से पछाड़ा। नॉर्वे की जेनेट हेग डुएस्टैड ने 347.6 अंक के साथ कांस्य पदक जीता, जबकि चीन की झांग लियुआन चौथे स्थान पर रहीं।

पुरुषों का स्कीट खिताब कतर के राशिद सालेह अल-अथबा ने जीता, जिन्होंने लगभग बेदाग प्रदर्शन किया।

पीएम मोदी ने दी भारतीय खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए शुभकामनाएं

विश्व केसरी

नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (सीडब्ल्यूजी) का आगाज हो चुका है। इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडब्ल्यूजी 2026 के लिए भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं दी हैं।

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो रही है, ऐसे में मैं भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी जोश, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन प्रदर्शन की भावना के साथ इन खेलों में हिस्सा लेंगे। हमारे खिलाड़ियों का हुनर ??और लगन हमेशा अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करते हैं।'

भारत के कुल 125 एथलीट्स इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि, इस बार बैडमिंटन, हॉकी, रेसलिंग समेत कई बड़े इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं हैं। भारत की ओर से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा निगाहें देश के 'गोल्डन ब्वॉय' नीरज चोपड़ा पर रहने वाली है। वहीं, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू से भी देश को पदक की आस होगी।

गुरुवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत की। इस दौरान मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना भारत की ध्वजवाहक रहीं। भारत के लिए टूर्नामेंट का पहला दिन शानदार रहा। बॉल्स प्रतियोगिता में भारत की पिंकी सिंह और रूपा रानी टिर्की ने दमदार प्रदर्शन करते हुए माल्टा की रेबेका लुईस रिक्सन और कोनो-ले रिक्सन की जोड़ी को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। वहीं, पुरुष टीम में पुतुल सोनोवाल ने उलटफेर करते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन रयान बेस्टर को हराया।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं।

पहले दिन बॉल्स प्रतियोगिता में टीम के शानदार प्रदर्शन की उन्होंने तारीफ की। खेल मंत्री ने अपने 'एक्स' पर लिखा, 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रोमांचक शुरुआत। आज एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें हमारे एथलीटों ने बॉल्स महिला पेयर्स इवेंट में माल्टा के खिलाफ आखिरी थ्रो पर शानदार जीत हासिल की।

वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप: अनाहत ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार कटाया सेमीफाइनल का टिकट

विश्व केसरी

ओंटारियो। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने मिस्र की हबीबा रिजक को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है।

महिला वर्ग की वर्ल्ड नंबर 20 खिलाड़ी अनाहत ने क्वार्टर फाइनल में हबीबा को 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराकर अंतिम चार में अपनी जगह बनाई। वह वर्ल्ड जूनियर्स में लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब उन्हें खिताब जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

सेमीफाइनल मुकाबले में अनाहत का मुकाबला मिस्र की ही बारब सामेह से होगा। इस बीच, बारब सामेह और मलिका एलकाराक्सी ने हांगकांग, चीन की हेलेन टैंग और बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम को सीधे गेम में हराकर अगले दौर में जगह बनाई। मिस्र के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एडम हवाल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सऊदी अरब के मोहम्मद अलनासफान को 3-1 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।

पुरुष वर्ग में मिस्र के मारवान असल ने कड़े मुकाबले में फ्रांस के अमीर खालिद-जौसेलिन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनके साथ मिस्र के ही दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया सलेम भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मलेशिया की व्हिटनी विल्सन को बेहद रोमांचक मुकाबले में हराया। यह मैच पांच गेम तक चला। दूसरी ओर, सेफेल्डिन रेफे (सीडिंग 3/4) ने मैडॉक्स मोक्सहैम को सीधे गेम में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रेफे का मुकाबला नंबर 1 सीड और अपने ही देश के मोहम्मद जकारिया से होगा। यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रींटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415